[Shri Mehr Chand Khanna]

No G S R 393/R-Amdt XXXXI dated the 4th April, 1959, making certain further amendment to the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules, 1955 [*Placed in Library. See* No LT-1371/59]

REPORT OF INDIAN PRODUCTIVITY TEAM

**The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah):** Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report of the First Indian Productivity Team on Productivity in Industries of U S A. West Germany and United Kingdom [*Placed in Library See* No LT-1372/59]

**12 30 hrs.**

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**SECRETARY** Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha —

"In accordance with the provisions of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 20th April, 1959, agreed to the following amendments made by the Lok Sabha at its sitting held on the 13th March, 1959, in the Chartered Accountants (Amendment) Bill, 1958

*Enacting Formula*

1 That at page 1, line 1 —

*for* "Ninth Year" *substitute*— "Tenth Year"

*Clause* 1

2 That at page 1, line 4.—

*for* "1958" *substitute* "1959".

**12.30½ hrs.**

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
### FORTY-THIRD REPORT

**Sardar Hukam Singh** (Bhatinda): Sir, I beg to present the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions

**12 31 hrs.**

## ESTIMATES COMMITTEE
### FIFTY-FIRST REPORT

**Shri B G Mehta** (Gohilwad) Sir I beg to present the Fifty-first Report of Estimates Committee on the action taken by Government on the recommendations contained in the Thirty-first Report of the Estimates Committee (First Lok Sabha) on the Ministry of Railways—Finance and Accounts

**12 31½ hrs**

## FINANCE BILL, 1959—*contd*

**Mr Speaker** The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri Morarji Desai on the 20th April 1959, that the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1959-60 be taken into consideration Shri Pahadia may continue his speech

**Some hon Members:** How much time is available?

**Mr. Speaker:** Shri Pahadia has taken three minutes The time allotted for general discussion is 11 hours out of which 9 hours 10 minutes have been availed of Therefore 1 hour 50 minutes now remain The time allotted for clause-by-clause consideration and third reading is 4 hours How long does the hon Minister propose to take for his reply?

**The Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** About 40 to 45 minutes

**Mr. Speaker:** We are now at 12 30' I shall call upon the Minister at 1-30 or thereabout.

Shri Pahadia may now continue his speech. If hon. Members confine their remarks to ten minutes I can provide for some more hon. Members.

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) अध्यक्ष महोदय कल वित्त विधेयक पर अपने तर्क जारी रखते हुए मैं यह कह रहा था कि प्रत्यक्ष कर जनता को ज्यादा न्यायप्रद हो सकते हैं चाहे उनके उगाहने में कुछ कठिनाई होती हो । उनमें एक खास बात यह होती है कि जनता पर इस बात की जिम्मेदारी आ जाती है कि वह देखे कि उनका ठीक तरह से उपयोग भी होता है या नहीं । इसलिये जैसा कि मैंने अर्ज किया न केवल इस देश के अर्थ शास्त्रियों की बल्कि संसार के बड़े-बड़े अर्थ शास्त्रियों की यह राय है कि अप्रत्यक्ष करों के मुकाबले प्रत्यक्ष करों का लगाना ज्यादा उचित है । लेकिन जब हम अपनी व्यवस्था को देखते हैं तो मालूम होता है कि अभी भी हमारे यहां प्रत्यक्ष करों का अनुपात अप्रत्यक्ष करों के मुकाबले में बहुत कम है । मैं आपको कुछ आंकड़े पेश करके यह बतला सकता हूं । सन् १९४४–४५ में हमारे यहां प्रत्यक्ष करों का अनुपात ४५ परसेंट था, सन् १९४९–५० में भी यह लगभग ४५ परसेंट रहा, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो तो सन् १९५३–५४ में यह केवल २४ परसेंट ही रह गया और आज सन् १९५८–५९ में इसका अनुपात ३१ परसेंट के लगभग है । हम देखते हैं कि इस वर्ष जो नये-नये कर लगाये गये हैं उनमें से २१ या २३ करोड़ के कुल करों में लगभग २० करोड़ की आमदनी अप्रत्यक्ष करों से होने वाली है । तो मेरा निवेदन यह है कि जहां तक हो सके मैं हमें अप्रत्यक्ष करों को कम करना चाहिये और प्रत्यक्ष करों को अधिक बढ़ाना चाहिये क्योंकि अप्रत्यक्ष करों में भ्रष्टाचार की ज्यादा गुंजाइश रहती है । लोग अप्रत्यक्ष करों को न केवल तरह-तरह से छुपाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन अफसरों को जिनके जरिये से इन करों को उगाहते हैं वे भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं । इस लिये मेरा निवेदन कि जहां तक हो सके हमको प्रत्यक्ष करों का ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

हम इन करों को अपना खजाना भरने के लिये नहीं उगाहते । इन करों को उगाहने में सरकार के तीन उद्देश्य हैं । एक तो यह कि देश की सुरक्षा रखी जाये, इसलिये करों की आवश्यकता होती है । दूसरा कर उगाहने का कारण है देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये रुपया एकत्र करना और तीसरा उद्देश्य जनहित की योजनाओं में लगाने के लिये रुपया एकत्र करना है जिससे कि देश का विकास हो सके ।

जैसा मैंने कहा अर्ज किया था हमें करों की व्यवस्था की ओर इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि आने वाली योजनाओं का और आने वाली पीढ़ियों का इन्हीं करों से काम चल सके । हमें करों को उगाहने की व्यवस्था में सुधार करना होगा । हम देखते हैं कि जब हम बाजार में जाते हैं तो हम सेल्स टैक्स देते हैं । पर हम देखते हैं कि कुछ दुकानदार पर्चे ही नहीं काटते । और खरीदार भी यह देखता है कि उसे दो पैसा का फायदा हो रहा है इसलिये वह भी कुछ नहीं कहता । और वह पर्ची के लिए आग्रह नहीं करता । हमें इस व्यवस्था की जांच के लिये कोई प्रबन्ध करना चाहिये ताकि यह टैक्स सही तरीके से वसूल हो । हमें इसकी जांच करने के लिये कुछ इनफारमर रखने चाहिये जिस तरह कि पुलिस इनफारमेशन ब्यूरो वाले रखते हैं ताकि वह हमको इस बात की सूचना दे सकें कि कि कहां-कहां पर चोरी हो रही है ।

रिपोर्ट को पढ़ने से मुझे मालूम हुआ है कि करों के उगाहने में बहुत ढिलाई हो रही है । हमें करोड़ों रुपये का कर उगाहना है और हमको मालूम है कि फलां-फलां व्यक्ति या फर्म से यह उगाहना है लेकिन फिर भी अभी तक यह कर नहीं उगाहा गया है । लगभग

[श्री पहाड़िया]

२६२ करोड़ रुपया वसूल करना पड़ा है । इसमें ढिलाई कैसे हो रही है यह मेरी समझ मे नही आता । हमें आज रुपये की कमी के कारण अपनी योजना मे कटौती करनी पड़ रही है, हमने ४८ अरब से योजना का खर्च ४५ अरब कर दिया है । अगर यह २६२ करोड़ रुपया हमको मिल जाये तो हम इसको योजना के लक्ष्यो को पूरा करने मे खर्च कर सकते है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो कर उगाहने में ढिलाई हो रही है इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो एरियर बाकी है उसे जल्दी से जल्दी वसूल किया जाना चाहिए ।

इसके साथ-साथ मै यह भी निवेदन करना चाहता हू कि जहा हम टैक्स बढाने जा रहे है और अधिक टैक्स उगाहते जा रहे है, वहा हमको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये कि उसका ठीक उपयोग हो । हम जो टैक्स बढाते है उससे धनीमानी और पूजीपतियो पर उतना बोझ नही पडता जितना कि जनसाधारण पर पडता है । और चूकि आपके करो का जनसाधारण पर भार पडता है इसलिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो कर जनता से वसूल किया जाता है उसका ठीक तरह से उपयोग हो यह न हो कि वह केवल अफसरो की तनख्वाहो पर और उनके भत्तो और मकानो की व्यवस्था आदि पर ही खर्च कर दिया जाय । आज हम देखते है कि कर बढता जा रहा है जबकि आमदनी का खाता लगभग बराबर ही रहता है । मालूम नही होता इतना खर्च किस तरह से बढता जाता है । कुछ समय पहले हमारे माननीय सदस्य श्री फीरोज गांधी ने ही यह बतलाया था कि केवल वित्त मंत्रालय मे ही १४ हजार कर्मचारी बढ गये है । अगर आपके पास इतने आदमियो का काम है तब तो उनको रखनी ठीक है लेकिन अगर उतना काम नही है तो इतनी सख्या नही बढानी चाहिये । मै अब कर्मचारियो के बारे मे तो यह नही कह सकता लेकिन कुछ तो दफ्तरों में आते हैं और कुछ समय बाद चले आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि दफ्तरो में बैठ कर गप करते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि हम कम से कम खर्च मे अपना काम चला सकें । मै यह बात इसलिये कह रहा हू कि हमारे प्रधान मन्त्री जी, चाहे वित्त मन्त्री जी या सदन के माननीय सदस्य जब गावो में जाते हैं तो किसानो को अपील करते हैं कि उन्हें पूरी मेहनत करके देश का अन्न का उत्पादन बढाना चाहिए । हमारे प्रधान मन्त्री जी ने तो यह नारा ही लगाया है कि आराम हराम है । तो मै यह जानना चाहता हू कि यह नारा केवल देहाती भाइयो के लिए ही है जो कि खेतो मे काम करते है या कि यह सरकारी कर्मचारियो के लिए भी है । मैं यह नही कहता कि आपका हर एक कर्मचारी भ्रष्ट है लेकिन कही-कही गलतिया है । इसलिय मेरा निवेदन है कि हमें इन गलतियो को दूर करने की ओर ध्यान देना चाहिए ।

यहा पर यह कहा गया कि ससद् के खर्च मे बहुत बढोतरी हो गयी है । पिछले सालो के आकडे देकर बतलाया गया कि कितना खर्चा बढ गया है । पर यहा पर भरूचा जी ने बतलाया कि सदस्यो की सख्या तिगुनी हो गयी है और इसलिय स्टाफ का तिगुना हो जाना भी मुनासिब बात है । तो ससद के बारे मे खर्च के बढने का तर्क कुछ जचता नही लेकिन वित्त मत्रालय के बारे में जो तर्क दिया गया है वह तो जचने वाला है । उसकी जरूर जाच करने की आवश्यकता है ।

इसके साथ-साथ मै यह निवेदन करना चाहता हू कि आज हम एक तरफ तो कर बढा रहे है और दूसरी तरफ लोन भी ले रहे हैं । साथ ही साथ योजना की कुछ मदो में कटौती कर रहे है । हमने सन् १९५६ से लेकर अब तक कोई २०० करोड़ रुपये का नया कर लगाया है । लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि यह

सारा खर्च हो जाता है और जब हम देखते हैं कि यह कहां खर्च हो रहा है तो हम देखते हैं कि बड़े-बड़े भवन बनायी जा रहे हैं उन पर यह रुपया खर्च हो जाता है, विकास के जो दूसरे काम हैं उन पर खर्च नहीं हो पाता । मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । योजना को गांवों से बनाना चाहिये और यह देखना चाहिये कि किसान की क्या जरूरत है, उसे अपने खेत के लिये क्या-क्या चाहिये इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । और उसके साथ ही शिक्षा का विकास भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा के बिना वह लोग यह निर्णय नहीं कर सकते कि कहां कट करना चाहिये ।

आप यहां दफ्तरों में बैठ कर योजना बनाते हैं इसलिये कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाये । पर इसके लिये आप अपने कर्मचारियों को हुक्म दे देते हैं । इस तरह आपका काम नहीं चल सकता । आपको तो देश की लगभग ४० करोड़ जनता का जीवन स्तर उठाना है । इसके लिये आपको अपने कर्मचारियों को हुक्म देना ही काफी नहीं होगा । आपको तो उस जनता को सलाह देनी होगी कि किस तरह से वह अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाये, तब काम चलेगा ।

इस काम के लिये आप बड़े-बड़े दफ्तर बनाते हैं । मैं यह नहीं कहता कि जहां जरूरी हो वहां भी आप दफ्तर न बनायें लेकिन जहां जरूरी न हो वहां उन पर रुपया खर्च न किया जाये । और उसे विकास के दूसरे कामों पर लगाया जाये ।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से हम रुपया बचा सकते हैं । मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि आज हम देखते हैं जो भी इमारतें बनायी जा रही हैं उनमें सीमेंट काम में लाया जा रहा है । देश में पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है उसको काम में लाया जा सकता है और इस सीमेंट को हम बचा कर बाहर भेज सकते हैं । आज देहातों में किसान के लिए भी सीमेंट भेजा जा रहा है इस ख्याल से कहीं किसान नाराज न हो जाये । मैं कहता हूं कि किसान नाराज नहीं होगा । उसके पास ककर है, चूना है, वह उसको काम में ला सकता है । हमारे यहां बहुत मैटीरियल पड़ा हुआ है जिसे काम में लाया जा सकता है और इस काम से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल सकता है । लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता । सरकार जिन चीजों को शहर को देना चाहती है, वह दे और गावों को जिन चीजों की जरूरत है, वह उन को दे । लेकिन जिस चीज की गावों को जरूरत है, वह सरकार न दे और जिस की जरूरत नहीं है, वह जरूर वहां पहुंचाये, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

हम कर लगाते हैं देश की शान्ति और सुरक्षा के लिये, लेकिन हम अनाज का बराबर आयात करते जा रहे हैं । जब इन टैक्सों से ज्यादा से ज्यादा काम लेना है, तो हमें देश की कृषि का विकास करना है । इसलिये यह जरूरी है कि .....

**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य समाप्त कर दें ।

**श्री पहाड़िया** . मैं एक मिनट में निवेदन कर देता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं जी ।

**श्री पहाड़िया** मैं आय पर प्रतिबन्ध लगाने की बात नहीं करता हूं । सरकार ने खेती पर सीलिंग लगाने का वादा किया है । लेकिन आप जानते हैं कि गांव के लोग अब उतने अनपढ़ नहीं हैं, जितने कि वे आजादी के पहले थे । वे सोचते हैं कि हमारी खेती और हमारी आय पर तो सीलिंग लगाई जा रही है । परन्तु शहरों के पूंजीपतियों के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है । मैं यह नहीं कहता कि उन पर टैक्स नहीं लगाया गया है लेकिन वह उस अनुपात से नहीं लगाया गया है, जिस अनुपात से लगाना चाहिये । वह आप को जल्दी से जल्दी लगा देना चाहिये ।

[श्री पहाड़िया]

आज हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें न केवल संसद् के सदस्यों के वेतन से बल्कि मंत्रिगण के वेतनों से ज्यादा हैं। वे इतने आराम के साथ रह कर कैसे देश का भला कर सकते हैं ? जितना आराम और सुविधा उन को चाहिये, वह जरूर देनी चाहिये, लेकिन अगर सम्भव हो, तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में कमी करनी चाहिये। नीचे तबके के कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि करनी चाहिये, जिन का गुजारा मुश्किल से हो पाता है और जिन पर हम आये दिन भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, जब इस देश में शिक्षा का प्रसार होगा, लोगो की नैतिकता जागेगी, तो भ्रष्टाचार कम होगा।

**Mr. Speaker:** The hon. Member's time is up.

**Shri Pahadia:** Just a minute.

**Mr. Speaker:** If any hon. Member persists in continuing with his speech after I ring the bell a second time, I will ask the reporters not to take down what he says. I cannot otherwise control hon. Members who go on speaking. The hon. Member wanted only 10 minutes. I gave him 20 minutes.

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देती हू कि आप ने मुझे भी दो दिन के बाद मौका दे दिया। हमारे बहुत से माननीय सदस्य जब विषयों पर बोल चुके हैं। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नही है, क्योंकि मेरे और भी भाई बोलने के उम्मीदवार हैं। मैं उतना ही कहूंगी, जितना कि हमारे देश के लिये हितकर होगा। हमारे भारत वर्ष को स्वतन्त्र हुए दस वर्ष हुए हैं। हम ने देखा है कि जो तरक्की इन दस वर्षों में हुई है वह पहले कभी भी नहीं हुई। और हमारे वित्त मंत्रालय ने देश की की जो तरक्की की है, वह लेखे से परे है। इस देश में और भी राज्य थे, ब्रिटिश जमाना भी था, परन्तु इतनी तरक्की इस में कभी भी नहीं हुई थी। जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, उन की बहुत तरक्की हुई है।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अभी बहुत काम बाकी है।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : मैं किसी का विरोध नहीं करती हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि इन दस सालों में हरिजनों की जितनी तरक्की हुई है, वह ब्रिटिश जमाने में कभी भी नही हुई। हम लोग कभी स्वप्न में भी पार्लियामेंट में आने की आशा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज एक देहात के रहने वाली को दूसरे माननीय सदस्यों के साथ बराबरी से बैठने का अखत्यार है। हमारे हरिजन भाइयो को भी चाहिये कि अब जब कि उन को उन्नति करने का मौका मिला है, वे गुटबन्दी मे न पड़े और एक साथ मिल कर काम करें। केवल हरिजनो में ही नही, हमारे बडे भाइयो मे भी—ब्राह्मणों और ठाकुरो में भी—गुटबन्दी है। जब तक इस गुटबन्दी को दूर नही किया जायेगा, तब तक देश का सुधार नही हो सकता है। हम सब को मिल कर पहले देश का सुधार करना है और सुधार उस जगह करना है, जहां पहले बिल्कुल नही हुआ है। उस जगह के लिये ज्यादा मांग नही करनी चाहिये, जहां अच्छी-अच्छी चीजें हैं, अच्छे-अच्छे मकान, मोटर, बसें और रेलें इत्यादि हैं उस एरिया पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिये। उस एरिया में ज्यादा पैसा लगाना चाहिये, जहां नहीं के बराबर काम हुआ है। अब सरकार को शहरों को छोड़ कर देहात में काम करना है, जहां हमारे किसान भाई रहते हैं। किसानों की तरफ से बहुत सा पैसा लगान में आता है, अबवाब में आता है और कई और टैक्सों से आता है। सरकार की ओर से शहरों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और वह देहात की तरफ नहीं बढ़ती है। इस कारण देहात की जनता बहुत निराश

हो गई है। वे कहते हैं कि ऐसा राज कभी नहीं हुआ, हमें बहुत तकलीफ है। हम उनको समझाते हैं कि हमारा पिछड़ा हुआ देश है, अंग्रेज लोग यहां से सब कुछ ले गये हैं, उन्हों ने कुछ नहीं छोड़ा है, हमारी सरकार और हमारी मिनिस्ट्री हमारी तरक्की के लिये काम कर रही है। देहात में तरक्की हुई है, लेकिन वहां काम सही तरीके से कामयाब नहीं होता है। हमारे कर्मचारी ईमानदारी के काम नहीं करते हैं, काम में रोड़ा अटकाते हैं। हमारे यहां बीज, तकावी, खाई, बंधिया या बैल का पैसा देर के मिलता है। इस के अतिरिक्त जब उस के लिये किसान दरख्वास्त देता है, तो पटवारी को पांच रुपये पहले चाहियें। फिर कचहरी में मुंशी को दस रुपये चाहियें। दस रुपये तहसीलदार को दिये जाते हैं, जिस से किसान को सौ रुपये के नब्बे ही मिलते हैं। हमारे किसान कहते हैं कि हम इतना टैक्स और लगान देते हैं, लेकिन हमारी हालत सुधरती नहीं है। उन की हालत कैसे सुधरे, इस का तरीका सोचना चाहिये। हमारी मिनिस्ट्री शहरों में रहती है, देहात में नहीं आती है। अगर वह गांवों के बीच में ठहरे और वहां किसानो की हालत को देखे तो उस को वहा की स्थिति का पूरा पता चल सकता है। होता यह है कि मिनिस्ट्री के लोग रैस्ट हाउस में ठहरते हैं, जहां लू बिल्कुल नही लग सकती है और जहा अच्छे ठंडे पानी का प्रबन्ध होता है। अगर उन को एक दिन तकलीफ भी हो, तो भी उन को गांवों के बीच में आना चाहिये। तभी हमारी जनता की समस्या हल हो सकती है मैं यह हंसी की बात नही कहती हूं और न ही झूठ बोलती हूं। जब मैं अपने एरिया में देहात में जाती हूं, तो वहां के लोग कहते हैं कि बाई, यहां की आवाज क्यों नही उठाई जाती है? मैं कहती हूं, भाई साहब, आवाज उठाई जाती है, बड़ी-बड़ी रिपोर्टें आती हैं, जो कि तुलें, तो तुल नहीं सकतीं, जिन को शेषनाग भी उठा नहीं सकता, लेकिन करें क्या? ऊपर से काम ठीक होता है, तो नीचे के कर्मचारी लापरवाही से काम करते हैं। अगर वे सचाई से काम करें, तो हमारे देश की समस्या हल हो सकती है। अगर हम उन की शिकायत करते हैं, लिख कर देते हैं, और वह डिपार्टमेंट के पास जाती है, तो वे लोग ऐसे मिल जाते हैं कि उस दरख्वास्त का, उस कागज का पता ही नहीं चलता कि वह किस कुंऐं में चली गई। अगर मिनिस्ट्री को लिखा जाये, तो यहां से सही कदम नहीं उठाया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि टैक्स चाहे लगाये जायें—जब टैक्स नहीं लगायेंगे, तो देश की उन्नति नहीं हो सकती है और देश का काम नहीं चल सकता है—लेकिन उतना टैक्स लगाना चाहिये, जिस से कि हमारी जनता के ऊपर भार न पड़े और हमारे देश का काम भी होता जाये।

अपने वित्त मंत्री महोदय से पहले मैं पूना में मिली थी। आज दूसरी बार उन से प्रार्थना करने का मौका मिला है। मैं उन से कहना चाहती हूं कि वह इतना टैक्स लगाते हैं, लेकिन वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरिया में डकैतियों की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। करोड़ों रुपये वहां लगाये जाते हैं, लेकिन डाकुओं और बदमाशों को खत्म नही किया जा सका है। उस समस्या को सींचते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर पौदा लगाते हैं। इस से वे समस्या कैसे हल हो सकती है? सरकार ऐसा आर्डर क्यों नही निकालती, ऐसा कड़ा कदम क्यों नही उठाती कि छ: महीने में डाकुओं का नाम लेश न रहे। विन्ध्य प्रदेश और राजस्थान में रेगिस्तान है, पहाड़ हैं। वहां कोई ऐसा रोजगार धन्धा नही है। वहां पर कोदों, कुटकी, लठारा, रागी, कौनी, मक्का, ज्वार वगैरह छोटा अनाज होता है और उसी पर वहां के लोग गुजारा करते हैं। वहां गेहूं, चना नहीं होता है। वहां पर छोटे छोटे धन्धे खोले जायें और इस तरह की स्कीमें वहां चलाई जायें। भिलाई में लोहे का कारखाना खोला जा रहा है। विन्ध्य प्रदेश में लोहे की बड़ी-बड़ी खानें हैं। वहां पर अच्छे रोजगार, छोटे छोटे धन्धे, छोटी-छोटी योजनायें चलाई जायें, जिस से लोगों को काम दिया जा सके

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

और वहां डकैतियां बन्द हो जायें । वहां के बुन्देले राजा थे । उन की बड़ी शान थी । वे कहते हैं कि हमारे राज्य चले गये, हमारे पास काम नहीं है, हम किस की मजूरी करें, हमारे लिये कोई चारा नहीं है सिवा इस के कि हम डाके डालें, हमें मिलिट्री में मौका दिया जाय, जिस से हम देश की रक्षा और उन्नति कर सकें । वहां के लोग यह मांग करते हैं । वहां पैसा लगाइये, टैक्स लगाइये ।

मैं ने आप का समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन आप घंटी न बजायें, क्योंकि मैं ने थोड़ा और भी बोलना है । आप उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे प्रदेशों में बड़ी-बड़ी नहरें और बांध देते हैं, जहां पर कि उन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि और जगहों पर है । हमारे विन्ध्य प्रदेश के लिये न तो कोई बांध ही दिया गया है और न कोई योजना ही बनाई गई है । राजस्थान में भी यही हाल है । वहां पर भी रेता ही रेता है । वहां पर मारवाड़ी लोग भी रहते हैं जो कि चार महीने तक अपने-अपने सामान अपने कंधों पर उठाये हिन्दुस्तान में घूमते फिरते रहते हैं क्योंकि पानी की कमी है । इस तरह के जो एरियाज हैं, उन में आप बांध बनाइये, वहां पर पानी का प्रबन्ध कीजिये पानी का वहां भंडार बनाइये । लेकिन आप पूरी हल्वा इत्यादि वहीं पर खाने को देते हैं, जहां पर कि खाने को मन नहीं होता है, वहां पर खाने को नही देते हैं जहां के हरिजन लोग भूखों मरते हैं । भौपा जाते हैं, टपरियों में हैं, जिन के पास रहने के लिये मकान नहीं है, खाने को चना नहीं है ।

अंग्रेजी पढ़ी लिखी मैं नहीं हूं . . . .

श्री डी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : बड़ी भाग्यवान हैं ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : हम ने कहा है न कि जब बुड्ढे हो जाते हैं, तब मति भी खराब हो जाती है । मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मुझे बोल लेने दी जिये और मुझे बीच में न टोकियेगा ।

मैं कहना चाहती हूं कि आप ने कंकसाये पर टैक्स लगाया है, वह अच्छा लगाया है, लेकिन उस को और कम कीजिये । कुछ लोग कहते हैं कि टैक्स लगने नहीं चाहियें, लेकिन मैं समझती हूं कि अगर टैक्स नहीं लगेंगे तो देश का काम कैसे चलेगा । जितने भी टैक्स लगते हैं, व्यापारियों पर या दूसरे लोगों पर, उन का बोझ जनता पर ही पड़ता है । अगर चार पैसा टैक्स लगाया जाता है, तो जनता पर ही इस का असर पड़ता है और कीमत को दो पैसा या इस से अधिक और बढ़ा दिया जाता है । लेकिन मैं मानती हूं कि टैक्स के बगैर देश का काम नहीं चल सकता है क्योंकि बड़ी-बड़ी योजनायें हैं जिन को पूरा किया जाना है और दूसरे बड़े बड़े काम करने को पड़े हुए हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहती हूं आज जरूरत इस बात की है कि देहात की हालत को सुधारा जाये और वहां पर जो किसान वर्ग रहता है, उस की जो मांगें है, उन को पूरा किया जाये । उन के लिये बिजली, पानी तथा छोटे-छोटे धंधे होने चाहियें और इस तरह की योजनायें आप बनायें और इस ओर कदम बढ़ायें ताकि जनता में उत्साह पैदा हो और वह पैदावार को बढ़ा सके । उनका जो काम है वह समय पर होना चाहिए । इस से हम जो सेवा कार्य करते हैं, उसमें अड़चन पैदा नहीं होगी । जब मैं सेवा-कार्य करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाती हूं तो मुझ से लोग कहते हैं कि बाई तुम हमारे लिए आवाज नहीं लगाती हो, हमारे लिए भी कुछ करो । मैं चाहती हूं कि उनको इस तरह की बात कहने का अवसर ही नहीं दिया जाना चाहिए ।

जहां तक शरणार्थियों का सवाल है, उनके वास्ते आपने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है लेकिन कहीं-कहीं पर उनके लिए रहने के लिए मकान नहीं हैं, तथा दूसरी सुविधायें नहीं हैं । मैं चाहती हूं कि उनके लिए भी आप कुछ करें । हमें उन्हें शरणार्थी नहीं कहना चाहिए, वे भी हमारे भाई हैं । मैं समझती हूं कि अगर मध्य

प्रदेश में या कहीं और शरणार्थी लोग हो जाते, तो उनकी समस्या इतनी आसानी से हल नहीं हो सकती है। लेकिन वे शरणार्थी कहीं पर भी किसी के मकान पर भीख मांगने के लिए नहीं गये। इन लोगों ने व्यापार में अच्छी तरक्की की है, अच्छा पैसा कमाया है और यह सब अपनी मेहनत से किया है। वे अपने ही पैरों पर खड़े हुए हैं और किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए नहीं गये। लेकिन दूसरे स्थानों पर, मध्य प्रदेश में जिन जिन जगहों पर शरणार्थियों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए और मैं चाहती हूं ऐसी जगहों पर आप पैसा लगायें ताकि वे भी महसूस कर सकें कि उनके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं।

जहां तक सिपाहियों का, मेजरों का या दूसरे लोग जो मिलिट्री में नौकरी करते हैं, उनका सम्बन्ध है, जब वे छुट्टी करके आते हैं, तब आपका कर्तव्य है कि आप उनको जमीन दें, घर दें, जगह दें ताकि वे काम करके अपना पेट भर सकें। २५-३० साल तक वे लोग मिलिट्री में काम करते हैं और नौकरी करने के बाद भी उनके लिए कुछ करना आपका कर्तव्य है। जो लोग मारे जाते हैं, उनके बाल-बच्चों की भी ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। डकैती एरियाज में देखा गया है कि जब कोई सिपाही मारा जाता है तो दो रुपया उसको इनाम का दे दिया जाता है या उसकी बीवी को दे दिया जाता है। अब दो रुपया में कौन अपनी जान गंवाना चाहेगा। उनके पूरे घर का आप बन्दोबस्त करें जिससे देश की रक्षा में कमी न आने पावे। वे लोग कहते हैं कि दो रुपये के लिए कौन काम करे। इस वास्ते मैं चाहती हूं कि इस ओर भी आप ध्यान दें।

चूंकि समय खत्म हो गया है, इस वास्ते अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आप सब का करके गांवों का दौरा करें और गांवों की हालत को देखें और गांवों की हालत को सुधारने के लिए जो कुछ हो सकता है, करें। जहां तक टैक्सों का सम्बन्ध है, आप खूब टैक्स लगायें, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हां, उतना ही लगायें, जितना कि लोग सहन कर सकें।

श्री वि० चं० सेठ (शाहजहांपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बराबर अब से वित्त मंत्रालय पर बहस हो रही है, यहां बैठा बहस को सुनता रहा हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार आदरणीय वित्त मंत्री महोदय के समक्ष रखे। मैं समझता हूं कि विचारों की इतनी बड़ी शृंखला है कि उन सब की तरफ वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री महोदय द्वारा ध्यान देना भी शायद सम्भव न हो सके। परन्तु मौलिक रूप से अगर इस प्रश्न को देखा जाये तो मैं ऐसा मानता हूं कि दो तीन चीजों की तरफ विशेष रूप से देखना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है।

सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी टैक्स लगाने की पालिसी निश्चित होनी चाहिए जिस के कि जनता में असन्तोष की भावना पैदा न हो। मैं बराबर ऐसा अनुभव करता रहा हूं कि बावजूद इसके कि आज कांग्रेस के हाथ में देश का शासन है, मैजोरिटी पार्टी के रूप में वही राज्य कर रही है, इतना होने पर भी अगर ध्यान से देखा जाये तो कोई भी वर्ग देश का ऐसा प्रतीत नहीं होगा जिसमें कि सन्तोष की भावना हो, फिर चाहे वे सर्विसिस हों, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यवसायी वर्ग हो या कोई और वर्ग हो। हर तरफ असन्तोष की भावना देश में फैल रही है। इसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, जहां तक मैं अनुभव करता हूं, वित्त मंत्रालय के ऊपर भी है। आज टैक्सेशन की पालिसी देश में इस प्रकार से चल रही है कि कोई भी वर्ग अपनी जगह पर निश्चित नहीं है। कितने आश्चर्य की यह बात है। जैसा कि मैं ने कुछ दिन पहले इसी सदन में कहा था कि आज जो बड़ी खेती कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में सीलिंग की बात की जाती है। हमारे देश में लोगों ने

[श्री वि० चं० शेठ]

बड़े बड़े फार्म बनाये, लाखों रुपया उन्होंने उन फार्मों को कामयाब बनाने के लिए लगाया लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि कल वे फार्म उनके पास रहेंगे या नहीं । इसके अतिरिक्त मैं दो चार और निहायत आवश्यक बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

कल एक प्रश्न आया था और मैं समझता हूं कि वह बहुत ही आवश्यक था । किसी एक सज्जन ने जर्मनी की उपमा दी थी जो तरक्की थोड़े समय में उसने की है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था । बड़ी ठीक उपमा थी । आज जर्मनी चार भागों में विभाजित है और चार देशों का जिस पर राज्य हो उसके बाद भी वह मुल्क इतनी तरक्की करता जाये और उसकी ट्रेड दुनिया के अन्य मुल्कों में फैलती जाये, क्या यह हमारे लिए लज्जाजनक बात नहीं है कि हम वैसा नहीं कर सके हैं ? इसके उत्तर में वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि यह चीज टैक्स पालिसी पर नहीं बल्कि देश के आदमियों पर निर्भर करती है कि कितनी तरक्की कोई देश करता है सत्य है । पर मैं एक बात कहना चाहता हूं । देश के अन्दर लोगों में इस तरह की भावना पैदा करना भी तो मंत्रियों का ही कर्तव्य है । इस देश को आजाद हुए बारह वर्ष हो चुके हैं । मैं तो बारह वर्ष नहीं मानता, अधिक मानता हूं क्योंकि पहली मिनिस्ट्री कांग्रेस की १९३७ में बनी थी । लेकिन बारह वर्ष ही आप मान लें । बारह वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में इस तरह की भावना पैदा हुई प्रतीत नहीं होती, जिसे देख कर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता । हर आदमी ऐसा मानता है कि जैसे कांग्रेस सरकार एक दूसरी चीज और जनता बिल्कुल दूसरी चीज । आज भी हम देश की जनता के अन्दर यह भावना पैदा नहीं कर सके कि यह देश हमारा है और हमारा भी कोई नैतिक कर्तव्य है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जर्मनी एक छोटा सा देश है और उसकी आबादी पांच करोड़ है जबकि हमारे देश की आबादी ३५-४० करोड़ और यह एक बहुत बड़ा देश है । इतना होने पर भी हम किसी भी प्रकार उस देश के सामने खड़े नहीं हो सकते इसका कारण केवल यही है कि हमारे देश के अन्दर जिस प्रकार की राष्ट्रीय मनोभावना होनी चाहिए, जिस प्रकार का उत्साह होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने हेतु उस उत्साह और मनोभावना का आज पूर्णतयः अभाव है ।

अब मैं एक और बहुत ही आवश्यक बात मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं । बरसों से यह बात चल रही है कि सारे देश में सेल्स टैक्स एक ही प्रकार से लगाया जाये । इतनी छोटी सी बात को करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को दो या चार घंटे की जरूरत है वह इस कार्य को करके एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते थे सारे देश के स्टेटों को वह इसके बारे में कह सकते थे परन्तु आज तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका । एक आदमी एक चीज कहीं से खरीदता है और दूसरी चीज कहीं और से । जनता को असुविधा न हो, इसका हम कोई इलाज आज तक नहीं कर सके । सारे देश के लिए सेल्स टैक्स की एक ही परिभाषा निर्धारित नहीं कर सके ।

अनेक वर्षों से सारे देश में यह भावना व्याप्त है कि वनस्पति को रंगदार कर दिया जाये परन्तु इसके बारे में भी कुछ नहीं किया गया । मेरी समझ में नहीं आया है कि कौन सा प्रभाव हमारे माननीय मंत्री महोदय के हृदय पर या मस्तिष्क पर पड़ा हुआ है कि इतनी छोटी सी बात को भी स्वीकार नहीं किया गया । ऐसा अगर कर दिया गया होता, तो जनता को प्रत्यक्ष तौर पर पता चल जाता कि यह शुद्ध घी और यह वनस्पति है । परन्तु आज तक भी हम इसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर सके हैं ।

12 hrs.

केवल विरोधी पक्ष ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों ने भी इस सदन में यह कहा कि आज खंडसारी पर जो टैक्स लगाया गया है वह बिल्कुल ही गैर जरूरी है। मैं यहां पर यह चीज बतलाना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पिछले दिन भी संक्षेप में अर्ज किया था, कि ३ आने रुपये की सब्सिडी दे कर हम सहर को जीवित रखना चाहते हैं तो उस का मुख्य उद्देश्य केवल यही होता है कि हम किसी प्रकार लाखों आदमियों की रोजी को कायम रख सकें। इसी तरह से खंडसारी के सम्बन्ध में है। खंडसारी पर आप ने जो रिलीफ दिया उस के लिए धन्यवाद है लेकिन वह ऐसी बात हुई कि एक आदमी पर दस सेर का बोझा लाद दिया जाय और अगर वह कहे कि हमें यह बरदाश्त नहीं तो कहा जाय कि अच्छा ९ मन कर दिया जाय। आखिर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ? खंडसारी आज देश में बिखरी गांव गांव में फैली हुई है। अगर हम उस को रिलीफ नहीं देते तो वह कैसे चल सकती है ? कभी कभी सोचने लगता हूं कि हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक शैली के अन्तर्गत शासन चल रहा है उस का सीधा और सच्चा अर्थ यही है कि प्रजा की भावना का आदर किया जाय। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि आज हमारे यहां के जो कर्ता धर्ता हैं उन के अन्दर एक ऐसी भावना बैठ गई है कि चूंकि उन्होंने निर्णय कर लिया इस लिए उस से हटने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां तक ठीक है एक ओर प्रजा-तांत्रिक शासन की घोषणा और दूसरी ओर उस के विपरीत मन में भावना निर्धारित कर उस से हटने की चेष्टा न की जाय ? यह एक दूसरे से मिलती जुलती बात नहीं है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन करूंगा कि सारे देश से अनेक प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन, आप के सामने आने का सीधा सच्चा अर्थ यही है कि आप के पास सब्र देखने टटोलने के लिए साधन है कि सारा देश यह चाहता है कि खंडसारी पर किसी प्रकार का कोई लेवी न लगाई जाय। परन्तु इन सारी भावनाओं को जानने के बाद भी मैं अनुभव करता हूं कि शायद अभी तक इस प्रकार की कोई चीज हमारे मंत्री महोदय ने अपने मन में निर्धारित नहीं की जिस से एकबुमनी कोई रिलीफ या सहयोग देश की जनता को प्राप्त हो सके।

यहां पर मैं एक चीज और आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि काटेज इंडस्ट्री को बढ़ाने के हेतू देश में बिजली फैलाई जा रही है। इस सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हमारे जितने भी मन्त्रालय हैं सभी चाहते हैं कि गांव गांव में बिजली फैलाई जाय। एक ओर तो हम बिजली फैलाने की कल्पना करें और दूसरी ओर जब कोई व्यवसाय बिजली ले तो उस पर नवीन टैक्स लगा दें। यह कैसी विरोधात्मक भावना है, मैं सोच नहीं पाता। अम्बर चर्खे तक में बिजली से चलाना की भावना लाई जा रही है कि उस को हम क्यों न बिजली से चलावें लेकिन दूसरी ओर यह हाल है कि सारे के सारे कार्यक्रम पुरानी पद्धति से किये जायें और केवल सेंट्रिफ्यूगल मशीन तीन हार्स पावर की चला दी जाय तो वह काटेज इंडस्ट्री टैक्स के अन्तर्गत आ जाती है। यह बातें मंत्री महोदय को स्वयम् समझना चाहिए था, जब सदन उन के सामने निवेदन करता है तो उन के हृदय में उन के लिए शायद कोई स्थान नहीं बना पाता।

प्लैनिंग कमिशन ने सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन में मिलो के लिए जो शूगर का कोटा निर्धारित किया था सन् १९५८-५९ में यह केवल बीस या साढ़े बीस लाख टन था। उस में से साढ़े उन्नीस लाख टन उन्होंने पूरा कर लिया इस तरह से वह लगभग अपने कोटे के टार्गेट तक पहुंच गये। परन्तु उन्होंने जो साढ़े सात लाख टन का खंडसारी का कोटा निर्धारित किया था उस में से वह केवल ढाई लाख टन केवल एक तिहाई तक पहुंच सका है। इस के

[श्री मि० चं० सेठ]

लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो केन्द्रीय सरकार का अंग है, ८ करोड़ रु० का बजट रखा था ताकि खंडसारी के सहयोग से हमारे देश में और लाखों लोग इस काम में नये लगाये जावें । एक ओर केन्द्रीय सरकार की अंग सरकार, व्यवसाय को मदद देने के लिये ८ करोड़ रु० का बजट निर्धारित करे दूसरी ओर हमारी केन्द्रीय सरकार है, जो कि उस सरकार के सर पर बैठी हुई, उस का गला दबा दे ताकि सारी की सारी इंडस्ट्री समाप्त हो जाय, मैं इन विरोधात्मक भावनाओं को देख कर कभी कभी बड़ा आश्चर्य करता हूं । आखिर तमाशा क्या है ? आप की ही एक अंग सरकार ८ करोड़ रु० से एक तरफ व्यवसाय को प्रोत्साहित करे और दूसरी ओर ऐसा टैक्स लगाया जाय कि सारे का सारा प्रोत्साहन वहीं का वहीं रह जाय, मैं अपने आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह बड़ी असत् बात होगी । आप को देश की भावना को साथ ले कर चलाना है । अगर आप देश की भावना का, एक पर्टिकुलर मामले में, जिस से देश के बजट पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, ऐसे मामूली मामले में, सत्कार नहीं करते, तो किस प्रकार कांग्रेस सरकार पर जनता का विश्वास हो सकेगा ।

यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फैक्ट फाईंडिंग कमिशन ने जो रिपोर्ट सरकार को दी, यद्यपि वह आज तक जनता के समक्ष नहीं लाई गई, परन्तु उस ने निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट में सरकार से कहा है कि कोई भी इस प्रकार का टैक्स खंडसारी पर लगाना, उचित नहीं होगा, बल्कि उन्होंने यह निश्चित किया कि २०० रु० पर बेस और ५०० रु० पर ज्यादा अधिक से अधिक, खंडसारी पर लाइसेंसिंग फीस कर दी जाय । यह निर्णय होने के बाद २५ फरवरी, १९५९ को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ३०० रु० पर बेस वाली जो सजेशन कमिशन ने दिया उस से १०० रु० अधिक, और ५०० रु० के बजाय ६०० रु० पर ज्यादा लाइसेंसिंग फीस लगा दी । अभी देश की रोशनाई भी सूखी नहीं थी कि वित्त मंत्री महोदय ने एक ऐसा टैक्स लगा दिया जिस के कारण जितने भी देश के इस कार्य के व्यवसायी थे सारे के सारे आतंकित हो गये । मैं उस क्षेत्र से यहां आता हूं जो कि सारे देश में सब से बड़ा खंडसारी बनाने का केन्द्र है । मैं वहां का रहने वाला हूं और इस लिए आप को बतलाना चाहता हूं कि हमारा वहां पर बैठना भी कठिन है । अनेक आदमी, तार, टेलिफोन सुबह से शाम तक आते हैं । मैं उन का क्या उत्तर दूं ? मेरे दिल में यह बात आती है कि मंत्री महोदय के पास मेरी विनय सुनने के लिए समय नहीं है यह ठीक उत्तर होगा । परन्तु यह उत्तर सुन कर उन्हें सन्तोष नहीं हो सकता । मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र के आदमियों की हालत बतलाऊं वहां पर क्या पोजीशन है । अगर यह मान लिया जाय कि यह टैक्स छोड़ दिया जाय और १ करोड़ या ७५ लाख रु० न भी लिया जाय तो उस से हमारे देश के कार्यक्रम पर कोई एफेक्ट नहीं होता परन्तु यदि देश की मनोभावनाओं का यही आदर प्रजातंत्रात्मक शासन में है तो मुझे कहना पड़ेगा कि इस के लिये किसी दूसरे शब्द की रचना की जाय वरना यह शब्द इस के लिये उपयुक्त नहीं है ।

**Shri Thirumala Rao (Kakinada):** Mr. Speaker, Sir, I rise to make a few observations on the Finance Bill in a general way. The proposals in the Bill have been subjected to a very critical examination by the different sections of opinion in the House. An impression is created that the tax proposals act heavily on one section of the public. There is an opposite opinion that this section is not sufficiently heavily taxed and therefore the hon. Finance Minister is partial towards them. But there is also a third opinion, which is more theoretical than practical, from my hon.

friend, who now and then treats this House to an intellectual exposition of the principle of socialism. He is not satisfied with anything that this Government has been doing. I believe that the situation lies somewhere in between all these contending criticism. But one thing is clear and that is that the Congress with its ideology and experience of administration over a number of years and with an intimate contact with the people has been steering the ship of State to the best of its ability and sincerity. Government can justly claim the approbation of the people at large and their allegience in the light of the substantial results achieved in the increased tempo of all-round development to achieve the final ideal of a socialist pattern of society.

The public sector as well as the private sector, both are absolutely essential for the development of this country. One cannot exist without the other. Up till now, that is, up to the time of our planning, the whole country more or less depended on the private sector excepting the public utility services run by the Government even during the British regime. Now, gradually the influence and the area of operation of the public sector is so developing that all public utility services are coming under public control, run for the people by the people and in the interests of the people. Therefore, one cannot say that the Government or the Party that is running this Government is not definitely marching towards the ideal of a socialistic State.

If you see the vast improvement that has been effected during the First Five Year Plan and during the first three years of the Second Five Year Plan, you will see how public investment has been stepping up by hundreds of crores of rupees every year. The very fact that the majority of the investments of Rs. 4,800 crores intended for the Second Plan go in the public sector shows that the main ideal of the socialist pattern is never lost sight of. But there is one thing and that is there that is no use in running down the private sector too. Important sections of industry are being controlled by the private sector. Textiles, tea, coffee, jute, sugar and all the foreign exchange earning part of our trade and commerce are in the hands of the private sector. There should be a harmonious co-operation between the Government and the private sector to see that until the Government and the people are in a position to take over the private sector in its entirety the private sector should not be strangled for want of proper encouragement.

We see that in 1956 Rs. 230 crores of new capital issues were sanctioned for the private sector, in 1957, Rs. 125 crores were sanctioned and in 1958, only Rs 80 crores. It is cut down. Therefore there is some legitimate grievance from the private sector that they are not able to get their heavy machinery and the essential raw materials to work up the factories to their full capacity and also to set up new plants to implement their programmes. There is no point in listening to the argument of my Communist friends that the private sector should be completely liquidated by the heaviest taxation possible. It has got a role to play until some time and, I hope, for a long time, if this country is to have a sort of a mixed economy.

We are not going on Western lines where heavy industry plays an all-important and all-enveloping role. We have to organise our industry in such a manner that there will be perfect co-ordination and co-operation between heavy industry, medium industry and cottage industry. Perhaps, China will be a good example for us to follow by having heavy plants in all the main sections of industry and medium-sized industries to be developed in villages and in smaller towns and cottage industries in villages. India, you know,—I need not say that—essentially is a land of the villages and we should all see that there should not be a general shift of population from the villages into towns to the detriment

[Shri Thirumala Rao]

for the dislocation of the economy of the whole country. We have to see that the rural economy is so geared up to industrial production that there will be plenty of production and consumption at the village level and at the smaller towns level as far as possible. That we are going on the right lines has been discerned by well-meaning friends from all over the world and I should like to quote one gentleman, who means much to us, who has been very helpful and who is no other than Mr. Eugene Black, President of the World Bank. He has commended India's measures to increase domestic resources for development plans. Mr. Black in his speech to be delivered in the United Nations Economic Council's Spring Session in Mexico said:

> "....a steadily expanding supply of essential public utility services was a 'requisite of economic growth in all under-developed countries'."

He has said:

> "If there is a strong base in domestic savings capital from outside it may provide that necessary margin of success in the development effort."

He cited Railways as an example. The Railways is a commercial concern that has its own capital, its own set-up and is ploughing back what it is earning into its development. Mr. Black has commended the Railways as an example where by the effort of the country and the Government of India they are able to maintain an essential services—not only maintain it but also develop it and meet all its development expenditure to a large extent. But we should be warned in time about the fall in the revenues or the anticipated income of the Railways both goods and passenger earnings. There is no use throwing the blame on road transport. Withdrawals from the Depreciation Fund for the five years ending 1959-60 average about Rs. 60 crores a year as against the annual accretion of only Rs. 45 crores as agreed to by this House. In the course of ten years, the total assets of the Railways will increase from Rs. 727 crores to Rs. 1,636 crores and a corresponding depreciation allowance has to be provided. But now we find that from Rs. 100 crores this Depreciation Fund has fallen to Rs. 37 crores. We have to carefully look into this matter and see that the anticipated incomes or earnings from the Railways will not fall but develop more and more.

Again, with regard to our electricity undertakings also they have to generate a self-paying tempo which prove in the next few years a paying proposition to the capital charges as well as the interest. That has to be done at any cost and in the initial stages we may suffer some losses but in the long run that is one of the essential services that has to be made as self-paying proposition.

With regard to huge river valley projects, in which hundreds of crores have been sunk, we must see that every drop of water which is generated in these projects is properly utilised and a corresponding wealth is produced out of which they pay their own interest and capital charges.

Thus, we see that the public sector is proving a successful proposition. But we are still in the initial stages. It requires experience. It requires knowledge. Essentially the question is not merely a question of money or resources but is a question of human capacity and personnel. That has to be trained in a large measure. We have seen many of these public undertakings that are being run by Government. For instance, the locomotive manufacturing concerns in the Railways, the coach factory, the aircraft factory, the fertiliser factory, some of these concerns are running well and are not incurring any heavy losses. But there are certain other concerns which are running into troubles in the earlier days but they have got the seeds of growth and development and can be very well improved by a

little more careful fending of them and careful attention being paid to the proper personnel posted in these undertakings. In all these public undertakings we have been noticing that there is a lack of competent accountancy system. Wherever we see we find enormous losses being incurred on account of faulty accounting. You require a large number of technical staff who are well-trained. There should be an automatic internal audit for every concern before these concerns run into troubles.

Then, I come to the question of land reform and co-operative agricultural activity. We have all agreed that agriculture is the base of all our structure and our economic growth. Without its development or without a proper organisation of agriculture, there is no use of planning in any other sector. But, our agricultural development has been always in trouble. The Agriculture Ministry—whoever has gone into that, has always had an unlucky star except probably Shri Kidwai in the recent decade.

**Dr. B. Gopala Reddi:** He also had; he met with his death.

**Mr. Speaker:** No, no. Not in that way.

**An Hon. Member:** He was there.

**Shri Thirumala Rao:** That was very brief. I never shared responsibility; I was a Junior Minister. All the criticism went to the Senior Minister.

**Shri Khadilkar:** Is it that the Junior Ministers do not share the responsibility?

**Mr. Speaker:** Not in his time.

**Shrimati Tarkeshwari Sinha:** Share responsibility, but not the blame.

**Mr. Speaker:** That is they are sitting in a separate Bench.

**Shri Thirumala Rao:** Our agricultural production is going up according to statistics. But, we are not able to cope with the varied situations that develop. We are not able to assure ourselves of any confident dealing with the situation. A degree of organisation and guidance with and by authority is needed in the chaotic condition of our present agriculture. The cooperation of a large number of people has to be enlisted or mobilised for the purpose.

If you see the figures from the National Sample Survey, the following data are revealed. The Sample Survey was carried out from July 1954 to March, 1957. There are 6·5 crores of families in India's villages. Under their control, there are 31 crore acres of land, which is nearly 38 per cent of the whole area of the country. But, it forms 61 per cent of the culturable area. Of these, 1½ crore families have no land at all. They are landless people. Of all the families in the villages, nearly one-fourth of them have got less than one acre per family, not per head. That is, one-fourth of the families are landless and one-fourth of the families own less than 1 acre per family. Of these families, 63·5 per cent work on their land; 12·5 per cent have partly leased out their lands. Only 2 per cent have completely leased out their lands and perhaps have gone to the towns following other professions.

**Mr. Speaker:** How many own below one acre?

**Shri Thirumala Rao:** One-fourth of 6·5 crores of families; they are families, not individuals.

The other 22 per cent of the people have no interest in any land. This is the deplorable condition of our agriculture today. Ninty per cent of the families are tilling their own land. Ten per cent of the families have joint ownership with others. Six per cent of the families do joint cultivation with others. Eight per cent of the land is in joint management.

I cannot understand the hue and cry raised against service co-operatives and co-operative farming. It is said that the leaders are depriving the poor peasant of his heritage handed down to him for centuries. I am sure this is not the voice of the poor, but the voice of the rich and middle

[Shri Thirumala Rao]

class rich on the threshold of the rich. They have got vested interests in absentee landlordism. If you go into the country and see, there are people owning 500 acres and 600 acres. There may be good farmers among them. There are hundreds of labourers working on their fields without any security of service or tenure for the next morning. This state of affairs cannot go on in the changing state of the world. Therefore, we have to devote some time to see how this system can be reformed and changed and transformed.

Acharya Vinoba Bhave has secured 40 lakh acres of land and 4,000 villages in Bhoodan. Whether it is useful land or not, is a different matter. But, it is a symbolic movement where without compulsion, out of free will so much of land has been given. Even if you want to do some charity, you may have a rejected coin and give it in charity. Some may have bought some useless land and given it in charity. If one wants to pass of as genuine person, he has got to show some charitable disposition. As you say, Sir, if you want to say Rama, Rama and become a Bhakta of Rama, even if you started saying mara, mara, it will become Rama Rama and you will be converted into a genuine bhakta. So also, for the sake of public policy, some people may have given the land. But the kibit of parting with land has been included as a proposition for 3 years which has attracted world attention today. Leaders of any country who have got the good of the masses at their heart, cannot ignore it for long. I do not want to say much. Government should devote more attention to large-scale farming. Here, in Suratgar, they are reclaiming 30,000 acres of land. In Terai area, they have already brought under cultivation 10,000 acres of land in the U.P. to settle the refugees from the Punjab. There is the tractor-ploughed land in Bhopal and Dandakaranya. There is in Mysore State what is called the Malnad Development scheme which can bring thousands of acres under cultivation. Such schemes can be brought up all over the country as part of the development plans under the Five Year Plan and we can see that production will increase.

Lastly, I want to say one or two things about the political situation. My hon. friends, yesterday, have been very loud in un-earthing some conspiracy or something in the Home Ministry department, financing a newspaper in Calcutta in 1953 and 1956. I want to remind my hon. friends opposite about this. Mr. Speaker, you were also here in this House when Mr. Maxwell was the Home Member. When we sitting in the House as Congress Members were being driven into detention camps, there were our members from the Communist party, hanging about in the ante-room of Mr. Maxwell, the Home Member. He financed them, purchased presses for them, supplied paper when there was paper scarcity and enabled the Communist party of India to run 13 language Indian papers all over India to discredit the Congress, to stab the Congress in the back, to hand over the Congress volunteers to the police. They believe that public memory is so short, and they un-earth something somewhere and hold up a skeleton. My hon. friend Shri Vasudevan Nair has got the tenacity and persistence to continue the old story that his friend started in the other House.

I want to say another thing, and this leads to the attitude of our Communist friends about Tibet and the recent happenings. It is nothing strange that their ideology is an exotic plant that thrives on periodical rejuvenation of their leaders undergoing medical and psychotherapeutic treatment in Moscow. One is not amazed to see that their love of their leader countries make them lose their sense of proportion to compare the Dalai

Lama with Master Tara Singh. There is nothing new.

But, it pains one greatly to note the tone and tenor of the speeches made by my hon. friend Shri Asoka Mehta. He is a good friend of mine. But, he does not know where he stands in the political field. He is so much bewildered. He is a leader of the Praja Socialist Party, having his body there, his soul in international politics and his performance between the Congress and the Praja Socialist Party. I was very much pained to see the lack of responsibility he has exhibited in a situation that is full of potential danger and delicacy. I shall quote one sentence from his speech—it is not a long one—made in the Sapru House—"Mr. Asoka Mehta, P.S.P. leader, said in New Delhi on Friday that India should not be satisfied by merely granting political asylum to the Dalai Lama, but should allow him to carry on his fight for freedom from here in a dignified manner." I credit him with vast knowledge and vast reading. He is periodically having refresher courses of his knowledge by visiting foreign countries.

Today, the position of India in the international world is delicate and trying. On the one side you have countries like Japan, America etc. in one camp and on the other, you have countries like Russia and China aligned on the other side of the camp. There are countries which are divided into two camps of cold war. Each camp is contending for intellectual and emotional superiority over men's minds. In this difficult situation, our hon. Prime Minister, with his extraordinary position in world politics, has created a position for India in the world which is at once respectful and forbidding for any powerful nation to meddle with our independence. The whole world has appreciated the role being played by our Prime Minister in this difficult time. The love, esteem and affection shown to Dalai Lama from Tejpur to Mussoorie speaks volumes for the sympathy and moral support that India has given to Dalai Lama in his difficult situation. It is not fair for any political party to fish in troubled waters, whether they belong to the socialist party or the communist party. All sections of the House have to give their support to our Prime Minister who is leading the whole nation in a delicate situation. His statement or his speech has not suffered in dignity or restraint. He has been discharging the duty that has fallen on his shoulders as an international statesman of great standing and repute. It cannot be possible for Dalai Lama to carry on his plans of regaining Tibet with India as his base of operations. The leader of the P.S. Party has been telling us that we are passing through a crisis of faith. I agree that it is a crisis of faith which my friends are passing through, today aligning themselves with the Communists in Orissa and the Congress in Kerala to reap some opportunist advantage.

**Shri Rajendra Singh** (Chapra): I am sorry to interrupt the hon. Member. Why does he forget that the Congress party is having political alliances with Akalis, Jharkand, Muslim League and Ganathantra Parishad?

**Mr. Speaker:** Order, order. The hon. Member is entitled to say what he wants to say.

**Shri Thirumala Rao:** I would request my hon. friends not to get excited. I was referring to the crisis of faith which has been so often preached recently by their leader.

**Shri Rajendra Singh:** The crisis of faith is right inside the heart of his own leader.

**Shri Thirumala Rao:** You do not lose your patience. I hope my hon. friends here will not lose their patience and get angry with me. We can talk about it in the lobby if he likes. But I wish to say this much that it is not fair for any political party to fish in troubles waters, whether they are socialists or communists.

I trust, Sir, the Finance Minister, on the whole, carries the goodwill of the House and the country in his arduous task.

**Mr. Speaker:** I would like to make an announcement. I would like to know the wishes of the House in this matter. Originally five hours had been allotted for clauses and Third Reading. I find that a large number of hon. Members still want to speak. Four hours have been set apart for the clause-by-clause consideration. There is time allotted for the third reading also. I do not know what need is there to have a lot of time for the third reading. So far as clause-by-clause consideration is concerned, I find that a number of amendments have been tabled . Most of the amendments are out of order because hon. Members want to vary the taxation proposals without the President's sanction. Therefore, those amendments are out of order. The hon. Deputy-Speaker originally allotted five hours. He took away some time from the clause-by-clause consideration. At the desire of the House, he transferred one hour from the time allotted for clause-by-clause consideration to the General Discussion. May I allot one more hour for the general discussion?

**Shri Raghunath Singh:** Yes. We will have a chance to speak.

**Mr. Speaker:** I will allow any hon. Member who has not spoken at the time of the general discussion to speak whatever he likes when we discuss the clauses.

**Shri M. R. Masani:** Before you pass final order, may I say something? The Finance Bill is an important Bill. The clause-by-clause discussion, in the view of some of us, has an importance. We should not treat that lightly.

**Mr. Speaker:** I will allow opportunity for the hon. Member to speak.

**Shri M. R. Masani:** Five hours were allotted for clause-by-clause consideration. It was reduced to four hours. I suggest that no further reduction should be made.

**Mr. Speaker:** If there is no amendment to clauses, why should any hon. Member go no suggesting that we must allow some time? There are no amendments. Most of the amendments are out of order. So far as the Government amendments are concerned, they are in pursuance of various representations which have been made and which certainly would be welcome to the House. Under those circumstances I do not think it is necessary. It was expected that the Finance Bill will be completed today by 6 o'clock. We took away half an hour for adjournment motion and for the short notice question. We started at 12.30. If we started at 12 o'clock we could have finished the clause-by-clause consideration and the entire third reading also by 6 o'clock. Now we have to sit for half an hour more. This evening we have got half an hour discussion on the question tabled by Shri Tangamani. I am going to allow that, but not today. Originally we agreed to sit till 6 o'clock until the Finance Bill is disposed of. On Friday, we will be sitting only up to 5 o'clock and we can take up half an hour discussion then. Tomorrow we have got two hours discussion. Originally I agreed that every week we will have a two hours discussion and half an hour discussion also. Without prejudice to either, we shall sit till 6.30 today and dispose of the Finance Bill. Now, one hour more will be taken up for general discussion.

Now, Shri Brajeshwar Prasad.

**Shri Brajeshwar Prasad** (Gaya): Mr. Speaker, Sir, a war between India and Pakistan can be averted only by the establishment of either the Delhi-Peking-Moscow axis or the Karachi-Peking-Moscow axis. The meaning of Delhi-Peking-Moscow axis is that Russia and China should publicly declare that in the event of a war between India and Pakistan, they would attack Pakistan. There will be no war between India and Pakistan if such a guarantee is given by Russia and China. Such a guarantee is in the interests of both India and Pakistan. I love Pakistan as much as I love this country.

**Shri Raghunath Singh:** Divided love.

**Shri Brajeshwar Prasad:** I am loyal to both India and Pakistan. The fact of political division cannot make any difference to my concept of a United India.

Russia will give this guarantee if we support Russian foreign policy *vis a vis* Europe and the New World. China also will give this guarantee if we withdraw recognition from those states which do not recognise her and if we remain outside the U.N.O. till she is admitted into it. It is in the interest of Europe also that we should support Russian foreign policy *vis a vis* Europe and the New World. If President Eisenhower's threat of nuclear destruction of Berlin is implemented, Europe, Russia, America and a large part of Asia will be obliterated. The first thing that the U.S.A. will do if such a war breaks out will be to destroy England, France and West Germany so that Western Europe does not pass into Russian hands.

The refusal of U.S.A. to recognise China or to admit her into the United Nations Organisation has in no way weakened China. It has, on the other hand, enabled her to work with impunity. China has become the largest, the greatest and the strongest power in the Afro-Asian landmass.

India will not be weakened if she stays out of the U.N.O. and withdraws recognition from those States which do not recognise China. If India and China come together, Chinese dependence upon Russia will be weakened, and the threat of a Russo-American settlement based on the division of the Afro-Asian landmass into two spheres of influence will be averted for ever.

America is bound to remain neutral in the event of a war between India and Pakistan, for, the basis of a political settlement between Russia and America is the division of the Afro-Asian landmass into two spheres of influence. Russia will have Africa and the Middle East, and America will have its hegemony over South Asia, South-East Asia and the Far East. And Russia cannot remain neutral in the event of a war between India and Pakistan, for the destiny of the heartland and the rimlands is intertwined.

Any American military adventure in the Indo-Pak continent will lead to the outbreak of a nuclear war on a global scale.

To the question of an average American why Russia is throwing nuclear weapons over America, the reply that America has intervened in Kashmir to defend democracy will be highly unconvincing and such a reply will be preposterous too.

No American Government can remain in power even for a few hours, if it provokes a nuclear war with Russia on the question of Kashmir.

**13.43 hrs.**

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

Limited wars are possible only in the Afro-Asian landmass. A global war is out of question. America cannot wage war against Russia either in Europe or in the Middle East. It can wage war against China only if Russia remains neutral.

India as much as China will stand to suffer if any war breaks out between China and America. Such a war cannot break out if India and China are integrated into one political unit on the basis of democracy. If a political settlement between China and Russia is arrived at, they also can wage limited wars in the Afro-Asian landmass.

A war between India and Pakistan may or may not be the result of a political settlement between either Russia and America or between Russia and China.

In the realm of practical politics, the alternatives to the Delhi-Peking-Moscow Axis are the establishment of

[Shri Brajeshwar Prasad]

either the Moscow-Washington Axis or the Moscow-Peking Axis. And both these alternatives constitute a threat to the black and the coloured races of the Afro-Asian landmass.

The net result of any conflict between India and China will be the establishment of either the Peking-Moscow Axis or the Washington-Moscow Axis. We have not come here to practise ashramite virtues; we are not bare bones; we are not going to jeopardise our territorial integrity in Kashmir for the sake of Tibet.

From a theoretical point of view, the alternatives to the establishment of the Delhi-Peking-Moscow Axis are the establishment of either the Delhi-Moscow-Washington Axis or the Delhi-Peking-Washington Axis. Both these alternatives are mere figments of imagination.

The interests of India and China on the one side and of America on the other clash in the Far East, South-East Asia and South Asia. And within the framework of the Delhi-Moscow-Washington Axis, the role of India would be that of a hewer of wood and drawer of water, for, the coming together of Russia and America connotes the establishment of Russian hegemony over Africa and West Asia, and of American hegemony over the Far East, South-East Asia and South Asia.

The threat of hegemony can be averted by the establishment of the Delhi-Peking-Moscow Axis and by no other means.

If a war breaks out between India and Pakistan, the result is bound to be the establishment of either the Delhi-Peking-Moscow Axis or the Karachi-Peking-Moscow Axis.

If the Delhi-Peking-Moscow Axis is formed now, the rimland will be integrated with the heartland on a democratic basis. The territorial integrity of India in Kashmir will be maintained intact; the power position of India will increase by leaps and bounds and the territorial integrity of Pakistan also will be maintained intact.

But if the Delhi-Peking-Moscow Axis is formed after the outbreak of war between India and Pakistan, the rimlands will be integrated with the heartland on a totalitarian basis; the territorial integrity of India in Kashmir will be maintained intact; the power position of India will be weakened; the State of Pakhthoonistan will be established; and America will be driven out of the old world.

But if the Karachi-Peking-Moscow Axis is formed either before or after the outbreak of a war between India and Pakistan, the rimlands will be integrated with the heartland on a totalitarian basis; Kashmir will be integrated with Pakistan; the power position of India will be weakened; America will be driven out of the old world, and Pakistan will become a satellite State of the Soviet Union.

A war between India and Pakistan is inevitable because there is no basis for an amicable settlement of the Kashmir question. We cannot jeopardise our territorial integrity in Kashmir. And Pakistan is bent upon grabbing Kashmir by fair means or foul.

A war between India and Pakistan is inevitable also because it is only through the mechanism of a series of limited wars throughout the Afro-Asian landmass that the *status quo* can be changed on the basis of either hegemony or a world State. The *status quo* in the Middle East in general and in Kashmir in particular cannot be maintained for long, for, it has outlived its utility. But the *status quo* cannot be changed either by a nuclear war on a global basis or by the method of consent. The *status quo* in Kashmir cannot be changed by the methods of subversion, infiltration, sabotage, murder and bribery.

A war between India and Pakistan is inevitable also because the aim of

American foreign policy is to weaken India, China and Russia, to separate them from one another and to make Asians fight amongst themselves The Baghdad Pact, the SEATO and the Ankara Pact are designed to weaken India, China and Russia

It is with the object of weakening India that the Kashmir question has been kept alive by the Western Powers in general and by the USA in particular It was with the object of weakening India that Pakistan was created. It is with the object of separating India from both China and Russia that the bugbear of communism is being dangled before our eyes It is with the object of separating India from China that the bugbear of the communes is being dangled before our eyes. It is with the object of separating Russia from both China and India that the threat of the yellow peril has been discovered by the Western Powers in general and by the USA in particular Mr Dulles once said that Chinese communism constituted a greater threat to freedom than Russian communism

A war between the Arabs, the Turks, the Iranians, the Afghans the Pakistanis, the Indians and the Chinese will facilitate the establishment of white hegemony over the Afro-Asian landmass

**श्री भक्त दर्शन** (गढवाल) एक किताब क्यों न छपवा दी जाये ?

**श्री रघुनाथ सिंह** (बागपत) किताब छाप दी जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** शायद वह पब्लिशर की तलाश में होंगे । अगर रघुनाथ सिंह जी पब्लिश करने के लिये तैयार होंगे तो उनको क्या ऐतराज है ?

**Shri Dasappa** (Bangalore). Let me come to certain realistic and mundane things from the flights of imagination which the previous speaker took

**Shri Brajeshwar Prasad:** It is due to lack of understanding that you consider it to be a mere flight of imagination

**Mr Deputy-Speaker:** Order, order That speech is concluded now I thought

**Shri Dasappa:** in traversing virtually from China to Peru

**Shri Brajeshwar Prasad:** You will never understand it

**Shri Dasappa.** I must congratulate the hon. Finance Minister for the very reasoned statement he has made about his Budget proposals. The House will remember how warmly the public received his proposals

People were rather afraid that there would be some very savage proposals of taxation, but when they saw the measures, it had a very reassuring effect on the country as a whole. That is by no means a mean achievement.

I would have liked to confine myself to the proposals before us but for the fact that there is one matter referred to by the hon Member from East Khandesh to which if I did not refer it would be inexcusable

In the course of his speech, referred to an agitation on the border between Bombay and Mysore, and he said 120 villages there had gone on a no-tax campaign, as if Mysore was some foreign or alien country and they were not the kith and kin of the people living on the border! Am I to think that because Maharashtra has got the whole of Gujerat in its hold today, they should start on a kind of satyagraha, civil disobedience, a no-tax campaign? I think if that had been done, there would have been some more justification than taking hold of a few villages somewhere on the Belgaum border

I am afraid he has not appreciated the position of Mysore There may be some other hon Members also who do not appreciate the position of Mysore We have never held that we

[Shri Dasappa]

are a mere linguistic State. We have got the whole of Kolar District where nearly 60 per cent. are Andhras, Telugu-speaking people.

**Shri Thirumala Rao:** So also Bellary.

**Shri Dasappa:** In Bellary it is not so much as in Kolar. Yet, we do not say that they are people who are foreign to us, and we do not see our Andhra friends laying claim to Kolar District. In fact, if I were to trace the history of the Diwans of Mysore right from 1881, you will find that *Rangacharlu and Seshadri Iyer*, were people from Tamil Nad. There was one Bengalee, Sir Albion Banerjee. Sir M. Visveswarayya and Nyapati Madhava Rao were Telugu people. Ramaswamy Mudaliar was both a Tamilian and a Telugu. The first elected Chief Minister of Mysore was my friend Shri K. C. Reddy who is a pucca Andhra, a Telugu person who comes from Kolar.

We want to bring about fine emotional integration in our country, and today here we see responsible persons, very important persons, for whose opinions I have the highest regard, making so much of a small thing like this. If there are differences, we will be able to decide these things, these small things, through negotiation. I am sure we have not abdicated our sense of justice and judgment in this matter.

**Shri Khadilkar** (Ahmednagar): Will you accept the arbitration of the hon. Deputy Speaker?

**Shri Dasappa:** I am not yielding to Shri Khadilkar These dramatic things are more meant for the gallary and the public outside and I am not going to yield to him.

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order. He has said he is not yielding, he is entitled to go on. No hon. Member should interrupt another hon. Member.

**Shri Dasappa:** So, I would very humbly beseech my friends who I think are mistaken in exaggerating a thing of this sort and lending strength to a thing which does not deserve any kind of support. On the other hand, it is up to us to tell them that this is not the way in which we should seek relief.

This satyagraha, no-tax campagin and civil disobedience were all right to win our freedom, but not to fight between ourselves and give rise to a lot of bad blood between ourselves. Therefore, I make a very humble appeal to our friends not to dwell on *these things*.

I would like now to come to certain proposals here. I would say one word about khandsari. I am on the Sugar Wage Board. We are taking evidence and giving consideration to the issues. That khandsari derived a tremendous impetus because of the doubling of the sugar duty in 1957 was brought home to us very emphatically. The only question I would put to those people who are still not satisfied with the reasonable stand of the hon. Finance Minister is: how did these khandsari units thrive before the sugar duty was doubled in 1957? What has the hon. Minister done? He has not tried to take away that duty which was levied afresh in 1957, but only a fraction of it. Of course, any taxation proposal meets with some opposition. There are so many big capitalists and others who are finding fault with some of the moderate proposals of the hon Finance Minister, but I say there is no justification for saying that the whole of the economy will suffer because of this small levy.

Next I would like to deal with art silk, and then I would say a word or two about cement.

**Mr. Deputy-Speaker:** All to be condensed within ten minutes.

**Shri Dasappa:** In another ten minutes, certainly.

**Mr. Deputy-Speaker:** Ten minutes in all.

**Shri Dasappa:** How much more time do I have?

**Mr. Deputy-Speaker:** Five more minutes.

**Shri Dasappa:** I will try to do the rather difficult job.

With regard to art silk, there has been a double duty. Firstly there is an enhancement of duty on yarn and staple fibre, both imported and indigenous. Secondly, the exemption limit has been reduced from nine to four looms, and now it is said only one for among the four looms will be permitted. Then, the duty has been raised from about Rs 54 for a shift per loom per month to about Rs. 77 and *pro rata* for the second and third shifts It comes to Rs 105 for three shifts

What is the margin of profit that, for instance, a nine-loom man will have? I have got the calculations, but I do not want to weary the House with them I will send them to the hon Minister later on. The profit on nine looms will amount to round about Rs 300 a month If this duty is levied, it will be about Rs 400-odd. The net result of it is that even a nine-loom man, with the present duty, will face a serious loss. I would therefore suggest one or two things

If you want to levy a duty, the easiest thing is—you will not lose the net advantage of the revenue that you want to get from your present proposals—to raise the duty on yarn used for weaving Every one who uses this yarn, whether he has four looms or more, will have to bear the burden in proportion That would be very easy to levy, and there will be perfect simplification. So, I would say restore the exemption limit of nine looms and have this levy, because the moment you say that only four looms will be fully exempted, the people will break up into smaller units I am making a very reasonable proposal. I do not know whether the hon. Minister is listening to me

**14 hrs.**

Last time he took up a certain attitude and levied certain extra duties on cotton power looms Let him at least apply to this industry the same principles which he has applied to cotton power looms; that is to say, have slabs, one to four, then five to nine, and then nine to twenty-five, and so on. Let him give some relief to the lower slabs, which do not make much money. I think anyone of these things can be done. Either he should enhance the duty on yarn to the extent of receiving the same amount of revenue as he is going to get from his present proposals; or have an exemption limit up to 9 Otherwise, have the slab system as in the case of cotton power looms

I would beg of the hon Minister to consider these proposals of mine which are not, in any way, going to reduce the income that he is going to get

Then, with regard to cement, we find a rather extraordinary situation I refer to what is happening in Mysore In Mysore, the Bhadravati Iron and Steel Works have a cement plant. The sale price is Rs 117'8- The basic amount allowed to the factory is Rs. 58,8|-; for packing and other things they allow Rs 12|- and it becomes Rs 70|8|- They take freight into calculation and give another Rs. 15|- So, the total comes to Rs 85|8'- Then, they have got a duty of Rs 24|- on every ton We do not know what happens to the amount of money between Rs 85'8|- and Rs 93|8|- I do not know who really gets the money The factory does not get it

Then there is another piece of grievous injustice The ACC is allowed 12 per cent profit while the Bhadravati Iron and Steel Works is allowed only 6 per cent. profit. Is it a sin on the part of the Mysore Government to have tightened up its belt and built up the industry?

**Shri Braj Raj Singh** (Firozabad): It is the love of the Government towards private business

**Shri Dasappa:** While the ACC is allowed 12 per cent, the Mysore concern is allowed only 6 per cent This seems to be terribly unconscionable Therefore, I would beg of the hon Finance Minister to reconsider the matter

There is one other matter of general importance to which I would refer and conclude The hon Finance Minister said, I think in answer to certain hon Members there, that the second Plan was conceived as a people's plan and the local authorities like the District Board and Taluk Boards or village panchayats were also consulted in the preparation of the Plan. True, he is a member of the Planning Commission, and that was the idea Those were the instructions that went round all over the country But I am saying on good authority that nothing of the sort was resorted to They were completely ignored with the result that today there is general criticism that the Plan does not evoke that amount of enthusiasm among the masses that it should

I am only saying this as a measure of c ion In drafting the Third Plan let us not ignore the people whose cooperation is absolutely essential to the success of the Plan Let us give them first what they want, to however limited an extent may be and then, by all means have these Sindris, Chittranjans and Hindustan Steels and so on Therefore I request that this aspect may be borne in mind so that the people may also feel the glow of freedom

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Khadilkar The hon Speaker had promised him only 5 minutes He left word with me that only 5 minutes were asked for

**Shri Khadilkar:** Yes, Sir, but I won't take more than 10 minutes

Mr Deputy Speaker, Sir, I will come to the issue raised by my hon friend Shri Dasappa, which I never imagined he would raise on the floor of the House, a little later

But today I would like to address the Finance Minister and the Ministry itself in a sort of pedestrain way Last time when I spoke I put an economic argument, and in support quoted some authorities An hon. friend from the opposite side said: Why quote authority? Later on I realised it is extremely difficult to carry on any argument with the Finance Ministry or with the Finance Minister or his deputies From his reply I could gather that I sometimes feel that in the present context the capitalist section in this country, is being represented by proxy in our Finance Ministry I would like to have really a direct representative like Mr Tata or Mr Birla sitting opposite as the Finance Minister—or even Mr Somani (he will be a good Minister)—and I do not mind that We will have a little more culture and refinement and we can argue with them matters relating to economic policy

**Mr Deputy-Speaker:** Why say these things why should the hon Member say more refinement and culture?

**Shri Khadilkar:** Bourgeoisie culture and refinement is well-known I am referring to that

**Mr. Deputy-Speaker.** He in a sense means that there is less culture and refinement in the Finance Minister and others That they would show more culture and refinement, by implication, means that the Finance Minister and the Finance Ministry or their officials are showing lack of culture and refinement There ought to be some dignity when we make speeches in this House and some decorum should be kept I take very strong exception to this

**Shri Morarji Desai:** I do not mind that

**Mr. Deputy-Speaker:** I am not concerned whether the hon Finance

Minister is worried about it or not. I have to look to my duty and I feel worried over it.

**Shri Khadilkar:** The only question was economic argument. I am going to refer to only one of the major points. The other day, while meeting the argument that I had advanced concerning the rise in expenditure of the Centre—the administrative expenditure—unfortunately, the Finance Minister advanced counter arguments. I do not know what you felt about it, but I think you indicated your mind. In my opinion that was deliberate by misleading of the House with a view to have our mouths shut.

I give the figures because he said that our expenses—that is Parliament's expenses—have gone up. He gave the figures for 1951 and the expenses for the current year. As I said, these figures were quoted with a view to show that we have increased our expenditure. It is but quite natural. In 1950, 1951 or the beginning of 1952, there was only one House and it was a transitional Parliament or the Provisional Parliament, as it was called. The membership was only 324. After the first General Election and, particularly, after 1956, after the reorganisation of the States, the membership has gone up to 787 of both the Houses put together. This is one part. Comparison, therefore, has no meaning at all, if we take the total membership of the former House.

Then the Lok Sabha came into being and started functioning. As I said on the last occasion, when it functions really effectively the responsibilities are bound to grow.

I would like to point out what the expenses then were and what they are now. That is very pertinent (*Interruptions*). At that time, in 1951, expenditure was only Rs. 32 lakhs. Today for the period 1959-60 it is expected to be Rs. 135 lakhs. These figures are relevant looking to the number and the added responsibilities and the various types of work we do. I think the proportion is well kept; the number has gone up more than two times and the expenses have gone a little more than that. This is one aspect of the matter.

There is another aspect. What is the position of a Member here if he wants to function effectively? What are the amenities provided to him? Unfortunately, the Demands of the Ministry of Parliamentary Affairs are not placed for discussion. If they were placed, we would have pointed out that in order to be functioning effectively we must be provided with better facilities.

From the point of view of distance we have been provided with almost no facility, because geographical conditions in India demand that more travel facilities should be given. The Minister of Parliamentary Affairs last time promised to reconsider all these issues. But while taking exception to this, I want to point out one thing today that this expenditure has gone up is misleading the House. I would like to give him another figure. During the last year and a half, the travelling expenses of the Central Government has gone up by more than Rs. 1·5 crores. Let him explain that position. The total expenditure incurred by the Central administrative departments on travel has gone up from Rs. 6 crores to Rs. 7·5 crores during one and half years. When administrative expenditure has gone up much more, should the expenditure that we incur on this Lok Sabha—which has a heavy and responsible work—be cited as an example? It is not meant to justify the growing administrative expenditure? To say the least—I do not want to use a harsh word it—is fantastic and unconvincing. I would like to have a reply from the Finance Minister

**Shri Morarji Desai:** If I reply, will he not complain afterwards of want of culture?

**Shri Khadilkar:** At the same time I would like to ask him about the

[Shri Khadilkar]

amenities provided for the Ministers. I know their responsibilities and they must be given all amenities. But if you really want every hon. Member to function as a responsible Member and contribute to the deliberations of this House, you should consider whether the amenities provided to the Members of the House are adequate or inadequate. In my opinion, they are inadequate. If you want to impose an austerity standard on the Members of the House, I am ready for it, provided the Ministers themselves and the administration are ready for an austerity standard which we demand for the country at the present stage of development.

**Shri Braj Raj Singh:** Nobody is talking of the Secretaries; the real thing is that.

**Shri Khadilkar:** My time is too short. Otherwise I would have referred to some points. I would now refer first to my hon. friend, Shri Dasappa. I do not consider it good—the happenings on the border. Last time, I have said that when between two States there is any dispute, such a dispute should be taken note of by this House. Why should this House abdicate its position as the final arbitrator? There is a quarrel about the border between Bombay and Mysore. Our Finance Minister is the architect of the Bombay State and he knows the genesis of the dispute very well. This House should take that into consideration and appoint an independent judicial authority to report back to the House. Or, as I said, I am ready if our Deputy-Speaker is entrusted with this task to find out the truth.

**Mr. Deputy-Speaker:** Has the arbitrator also any voice or not, whether he accepts it or not?

**Shri Khadilkar:** We would request on behalf of both sides. Immediately, I can tell my friend, the no tax campaign will be withdrawn within no time. Is he ready?

**Shri Dasappa:** It is the House which has decided it.

**Shri Khadilkar:** This House once decides. But when it discovers that the decision is wrong, that it was tainted by certain party manoeuvres and power manoeuvres, certainly this House has every right to revise that decision. Therefore, I would appeal to this House to appoint some judicial authority and take the initiative and settle the dispute, and the Samyuktha Maharashtra Samiti would not proceed with its struggle.

One word more regarding the Finance Bill. The new taxation proposals raise the tax on lower slab regarding wealth from half a per cent to one per cent. The upper slabs are there. Last time when these measures were discussed, I pointed out what would be the effect of this taking the estate duty, wealth tax, etc. together on the middle-classes. I would like to point out to the Finance Minister that the effect would be disastrous We on our side always find the Deccan Queen. There are now third-class, first class and servant-class compartments. There we see the picture of the present society. There is the top class and the rest are the servant or third class. The second class on the railways has been abolished. The middle-classes in this country, those who really contribute to the cultural education and so many other social aspects of life are having an unnecessarily heavy tax burden. An attempt is being made to practically to liquidate the middle class, by making that class insolvent. Therefore, I would appeal that so far as this lower slab is concerned, this raising of the limit from half per cent to one per cent is a big jump which would affect that particular class and it should be reconsidered.

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Vajpayee. I have to remind every hon. Member that the limit is ten minutes.

**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर विचार करते

समय यह स्वाभाविक है कि हम देश की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में कुछ विचार करें, और भवष्य में देश का आर्थिक निर्माण किस दिशा में किया जा रहा है इसके बारे में सोचें। इस समय तृतीय पचवर्षीय योजना की चर्चा चल रही है। उसका रूप क्या होगा इसका निर्धारण योजना आयोग को करना होगा। योजना आयोग का निर्माण किस तरह से किया जाय इसके सम्बन्ध में आकलन समिति ने, एस्टिमेट्स कमेटी ने, कुछ सिफारिशें की थी। उसका मत है कि योजना आयोग में मंत्रियो की सख्या अधिक नही होनी चाहिये। प्रधान मंत्री, सुरक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री, योजना आयोग में यदि रख दिये जायेंगे और बाद में योजना आयोग द्वारा बनाई हुई योजना मत्रिमंडल के विचार के लिये आयेगी तो मै नही समझता कि मंत्रिमंडल उसमें कोई व्यापक रूप से सशोधन या परिवर्तन कर सकता है। यह खेद का विषय है कि एस्टीमेट्स कमेटी की इस सिफारिश को स्वीकार नही किया गया। इतना ही नही, प्रयत्न तो इस बात का किया जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से योजना आयोग का कार्य सत्तारूढ दल के अधिकाधिक नियंत्रण में चले। होना तो यह चाहिये था कि योजना आयोग में से मंत्री कम किये जाते और आर्थिक मामलो के विशेषज्ञ, जो किसी एक पार्टी से बंधे हुए न हो, योजना आयोग में लिये जाते, किन्तु अभी योजना आयोग में जो नियुक्तिया हुई हैं उनमें हमारे इस सदन के एक सदस्य लिये गये है और एक सदस्य ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व सेक्रेटरी है। मुझे उनकी योग्यता के बारे में कुछ नही कहना, किन्तु प्रश्न यह है कि यदि हम योजना सर्वोत्तम रूप की बनाना चाहते है और इस योजना को सफल बनाने के लिये सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रेरणा और उत्साह पैदा करना चाहते है तो योजना आयोग में सत्तारूढ दल के व्यक्तियो का बहुमत इस दिशा में सहायक नहीं हो सकता।

एक बात और है। ऑल इडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। उसमें योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन श्री वी० टी० कृष्णमाचारी भाग लेते है। मैं समझता हू कि यह पद्धति बहुत आपत्तिजनक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कांग्रेस का नियन्त्रण करती है और उसी कांग्रेस की देश में सरकार है। किन्तु लोकतन्त्र में पार्टी और सरकार में एक विभाजन रेखा होनी चाहिये और इस को अगर मिटाने का प्रयत्न किया जायेगा तो यह लोकतन्त्र पर कुठाराघात होगा। मै जानना चाहता हूं कि अगर देश में और भी पार्टियां अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में योजना आयोग के डिप्टी चेअरमैन को भाषण करने के लिये बुलायें, अपने विचार रखने के लिये निमन्त्रण दें, तो क्या वे उस निमन्त्रण को स्वीकार करेंगे या वे केवल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में ही जाना ठीक समझते है? मै समझता हूं कि अगर सच्चे अर्थों में नव निर्माण की योजनाओं के प्रति उत्साह पैदा करना चाहते हैं तो योजना के दलीय स्वरूप को समाप्त करना होगा और केवल योजना के निर्माण में ही नही परन्तु उसके क्रियान्वित करने में व्यापक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिये।

अभी केन्द्र में तृतीय पचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिए एक सर्वदली समिति बनी है मगर उसकी कोई बैठक नही हुई है और मुझे आशंका है कि भविष्य में बैठक होगी या नही। यह तभी होगी जब योजना की पूरी रूपरेखा निश्चित कर ली जायगी। मै समझता हूं कि शासन की ओर से इस दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिये।

इस सम्बन्ध मे एक बात और है। इस सदन में इस बात की काफ़ी चर्चा हुई है कि सरकार अपने खर्चे में कमी करे। सिविल एक्सपेंडिचर जो बढता जा रहा है उसमें थोड़ी सी कटौती होनी चाहिये। लेकिन मैंने समाचारपत्रो में पढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी ने सरकारी खर्चे में कमी करने के लिए एक

[ श्री वाजपेयी ]

कमेटी बनाई है जिसके कि अध्यक्ष श्री फ़िरोज गांधी हैं। मैंने यह भी सुना है कि वह कमेटी सरकारी फ़ाइलों को देख रही है और सरकार का खर्चा किस तरीक़े से बढ़ गया है उसकी जांच कर रही है और किस तरीक़े सेवह कमहो सकता है इसके बारे में सुझाव दे रही है। खर्चा कम करने के सम्बन्ध में अगर कांग्रेस पार्टी कोई सुझाव देती है तो उसको इसका अधिकार है और उसका स्वागत किया जाना चाहिये लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई कमेटी सरकार की फ़ाइलें देखें, सरकारी अफसरो से इंटरव्यू करे और खर्चा किस तरीक़े से कम किया जा सकता है इसकी चर्चा करे तो मैं समझता हू कि यह उसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जिसके कि अन्तर्गत सत्तारूढ़ दल देश के जीवन पर पूरी तरह से हावी होना चाहता है। मै मानता हूं कि सरकारी खर्च में कमी की बहुत गुंजाइश है और जो कमी की गई है उससे भी अधिक कमी की जा सकती है लेकिन किसी पार्टी की कमेटी सरकारी कामकाज में इतनी दखल दे इसे मैं लोकतंत्र की दृष्टि से उचित नहीं समझता।

**Shri Morarji Desai:** May I give some information in this connection? They are not allowed to see any papers or anything of that sort. They do not go and see them. If they ask for any information that is supplied to them. If the hon. Member wants any information that also is supplied. Therefore, there is no question of treating them in a special way or giving them a special position.

**Shri Vajpayee:** Is it a fact that they are asking officers to appear before them?

**Shri Morarji Desai:** No, Sir.

**Shri Vajpayee:** Sir, I stand corrected.

इस सरकार द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान से जो पुरुषार्थी आये हैं उन्हें पूरी तरह से बसा दिया गया है और अब यहां जहां तक पुनर्वास मंत्रालय के पश्चिमी पाकिस्तान के विभाग का सम्बन्ध है उसे बंद कर दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ा दावा है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को स्वीकार करे कि उसने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये पुरुषार्थियों को बसाने के लिए अब तक जो कुछ किया है उसको कसौटी पर कसने के लिए एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त किया जाय। लोग बसाये गये हैं इसमें संदेह नहीं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बसाया नहीं गया है और जो भी धन का खर्चा किया गया है, करोड़ों की राशि में है क्या उस धन का सदुपयोग हुआ है? क्या पाई, पाई उसकी ठीक तरीक़े से खर्च हुई है, इस बात की भी जांच होनी चाहिये।

प्रधान मंत्री जी की कोठी के सामने बहुत से पुरुषार्थी भाई इस समय धरना दिये बैठे हैं। किसी को धरना देना अच्छा नहीं लगता लेकिन उनके सामने संकट है और वह यह कि मकान व दुकानें जो पुनर्वास मंत्रालय ने बनाई हैं उन पुरुषार्थियों को नो लौस नो प्राफ़िट बेसिस पर देने के बजाय उनको नीलाम किया जा रहा है। अब नीलामी में उन मकानो और दुकानों की क़ीमतें बढ़ जाती हैं और पुरुषार्थी भाई अपने सीमित साधनों से उन दुकानों और मकानों को प्राप्त नही कर सकते। होना यह चाहिये था कि सरकार जिस लागत पर उसने मकान और दुकान बनाये हैं उन पर पुरुषार्थी भाइयों को देती लेकिन सरकार पुरुषार्थी भाइयों से मुनाफ़ाखोरी कर रही है। किस्तों में जो ऋण दिया गया है वह वसूल किया जाय इस सम्बन्ध में भी उनकी मांग अभी तक मानी नहीं गई है।

हमारे देश में पब्लिक सैक्टर को बढ़ाने की बातें कही जा रही हैं। मैं पब्लिक सैक्टर का विरोधी नहीं हूं लेकिन अभी तक जिस

जिन क्षेत्रों में हमने हाथ डाला है उनमें कोई हमने बहुत खूबी से काम करके दिखाया हो, ऐसी बात नहीं कही जा सकती। १३ पब्लिक इंटरप्राइजेज का हिसाब किताब इस सदन के सम्मुख रक्खा गया है। उससे पता चलता है कि एक सिंदरी की फ़र्टिलाइज़र फ़ैक्टरी को छोड़ कर कोई भी पब्लिक इंटरप्राइज़ अच्छे तरीक़े से नहीं चल रही है। सिंदरी फ़र्टिलाइज़र फ़ैक्टरी में भी जो मुनाफ़ा हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि किसानों से खाद के अधिक दाम वसूल किये जा रहे हैं। अगर वह दाम ठीक वसूल किया जाय तो शायद उसका मुनाफ़ा भी खत्म हो जायगा। मेरा निवेदन यह है कि पब्लिक सैक्टर को बढ़ाने के बजाय जो उद्योग सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं उनको ठीक तरीक़े से चलाये, उनको सफल बनायें और जो व्यक्तिगत उद्योग हैं उन पर नियन्त्रण रखे, नियमन रक्खे और उनमें मुनाफ़ाखोरी को रोके। लेकिन सरकार सर्वाधिकार अपने हाथ में ले ले तो आज की स्थिति में वह न तो सफल हो सकती है और न लोकतंत्र की दृष्टि से उसे वांछनीय ही कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं एक्साइज ड्यूटी के बारे में कह दूं। वित्त मंत्री महोदय ने खंडसारी पर थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी मगर मेरा निवेदन है कि वह पर्याप्त नहीं है और उससे छोटे उद्योगों को जितनी सहायता मिलनी चाहिये उतनी सहायता प्राप्त नहीं होगी। असली समस्या तो उस एक्साइज ड्यूटी की वसूली से उत्पन्न होने वाली है। क्या छोटे छोटे कारखानेदार अलग अलग रजिस्टर रखने के लिये बाध्य होंगे? क्या एक्साइज ड्यूटी इंस्पैक्टर उन्हें परेशान नहीं करेंगे। क्या वसूली में सरकार का उतना खर्चा तो नहीं हो जायगा जितनी कि कुल मिलाकर आमदनी भी नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि इस वसूली की पद्धति को कुछ सरल किया जाना चाहिये और अगर एक मुश्त रक़म ली जाय और जो तेल वाले हैं, खंडसारी वाले हैं या नक़ली रेशम वाले हैं उनको वसूली के झंझट में न पड़ना पड़े तो मैं समझता हूं कि उद्देश्य भी पूरा हो जायगा और वसूली में भी सरलता होगी।

**चौ० रणबीर सिंह (रोहतक)**: उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में कुछ दोस्तों द्वारा यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि देश तरक्की नहीं कर रहा है और सिर्फ करों की वसूली ही की जा रही है। लेकिन अगर जरा आंकड़ों को देखा जाय तो पता लगेगा कि सन् ३८, ३९ में हिन्दुस्तान की सरकार का रुपया जो यहां सरकारी कारोबारों में लगा हुआ था वह ७५२ करोड़ था और केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को जो रुपया दिया था वह १२३ करोड़ था लेकिन सन् १९५९-६० के आखिर में जो रुपया हिन्दुस्तान की सरकार का सरकारी कारोबारों में लगेगा वह २१३५ करोड़ होगा और केन्द्रीय सरकार जो सूबों की सरकारों को रुपया देगी वह १६२८ करोड़ होगा।

इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि देहातों की तरक्की के लिए नहरों द्वारा पानी की उचित व्यवस्था की जानी जरूरी है। हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद हिन्दुस्तान के हिस्से में इरिगेशन के लिए जितने काम आये थे उन के ऊपर कुल ११० करोड़ रुपया लगा हुआ था। दूसरी पंचसाला योजना के बाद जो रुपया इरींगेशन को बढ़ाने के लिए खर्च होगा या जितने प्राजेक्ट्स पर रुपया लगा होगा वह ७२१ करोड़ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि देश आगे बढ़ रहा है, भिलाई में और रूरकेला में बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें हैं जिन पर हमें गम्भीरता के साथ विचार करना होगा।

पहली पंचसाला योजना में हम ने विदेशों से जो कर्जा लिया या डैफिसिट फाइनेंसिंग के

[श्री० रणवीर सिंह]

जरिये जो रुपया हासिल किया वह सिर्फ ३६ फीसदी था । लेकिन दूसरी पंचसाला योजना के अन्दर जो हमारा अन्दाजा है उसके मुताबिक वह ६३ फीसदी बैठेगा । इसके साथ साथ यह भी गौर करने वाली बात है कि सन् १९४६ के बाद से लेकर सन् १९५८ तक देश के अन्दर जो अनाज बाहर से आया है वह १४५६ करोड रुपये का था । इसके अन्दर अगर यह भी मान लिया जाये कि ३५० करोड़ के करीब का जो अनाज आया वह उधार पर या मदद के तौर पर आया, तो भी ११०० करोड रुपया बाहर से अनाज मगाने पर खर्च किया गया । इसके साथ साथ उस अनाज को सस्ता बेचने के लिए जो रुपया खर्च हुआ वह २६१ करोड था । वह या तो सबसिडी के शक्ल मे था या सहायता के तौर पर था ।

मुझे खुशी है कि आज हिन्दुस्तान के वित्त मंत्रालय के मत्री श्री मुरारजी देसाई श्री गोपाल रेड्डी, श्री बलीराम भगत और हमारी बहिन है । ये सभी साथी देहात में पैदा हुए हैं और इनका किसानो मे सम्बन्ध रहा है । दो का तो बम्बई और आन्ध्र के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से किसानो मे सम्बन्ध रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मै अर्ज करना चाहता हू कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर पानी बढ़ाने के लिए मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट चलाये जा रहे है । उन पर करोडो रुपया खर्च किया जा रहा है । यह अन्दाजा लगाया गया है कि सैकिंड फाइव इयर प्लान के बाद कोई तीस चालीस करोड़ साल का ब्याज का खर्चा इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पडेगा । आपको मालूम ही है कि हिन्दुस्तान का सब से बडा प्रोजेक्ट भाखरा का है । वह सन् १९४६ में शुरू हुआ था और सन् १९६१ में जाकर कहीं पूरा होगा । इस तरह १४ या १५ साल उसके बनाने में लगेंगे और अन्दाजा है कि १४ या १५ साल लगेंगे जब कि उसका पूरा फायदा उठाया जा सकेगा । आपको मालूम ही है उस पर १७० करोड़ रुपया खर्च होने का अन्दाजा है और उसके ऊपर जो ब्याज का खर्चा पडेगा वह ५० करोड के करीब बैठेगा । जिसका मतलब यह है कि जब वह प्रोजेक्ट खत्म होगा तो उस पर २१ फीसदी खर्चा जो पड़ेगा वह ब्याज का होगा । दूसरी तरफ हम देखते हैं कि २६१ करोड की इमदाद दी जाती है अनाज सस्ता बेचने के लिए । यही नही, मैं ने हिसाब लगाया है कि सन् १९४८-४९ और सन् १९५६-५७ में सरकारी नौकर को, सिर्फ सैंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिमो को, जो इमदाद डिअरनैस अलाउंस की शक्ल में दी गयी वह ५१ करोड रुपया और ८८ करोड रुपया बैठती है । इसके अन्दर उन सरकारी कर्मचारियो का अलाउंस शामिल नही है जिनको कि १००० से ऊपर तनख्वाह मिलती है । जो हमारे आई० ए० एस० के भाई नौकर होते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नही है जिसको तनख्वाह के अलावा २०० रुपये का अलाहिदा अलाउंस न मिलता हो । उनमे से तकरीबन हर आदमी को २०० रुपये का अलाहिदा अलाउंस दिया जाता है । इसके अलावा जो दूसरा पे कमीशन बैठा है वह शायद ४० या ६० करोड के करीब का खर्चा बढायेगा ऐसा अन्दाजा है । तो आज हिन्दुस्तान में अनाज की पैदावार कम होने की वजह से हिन्दुस्तान की सरकार को अपने कर्मचारियो को १०० या १२५ करोड रुपया महगाई भत्ते के रूप में देना पड रहा है । यह सिर्फ हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो को ही दिया जाता है । दूसरी तरफ हम सबसिडी देते हैं । लेकिन यह जानकर ताज्जुब होता है कि पानी बढाने के लिए जो सबसिडी दी गयी है वह सात साल के अन्दर कुल ११ करोड रुपया है । मैं चाहता हू कि हिन्दुस्तान की सरकार इस बात पर शान्ति से गौर करे कि अगर वह मेजर और मीडियम इरिगेशन प्राजेक्ट्स को लोगों की भलाई के लिये चलाना चाहती है

तो टैक्स उगाहने की ठीक व्यवस्था करे । हम योजना को चलाने में सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग किसानों को भड़काते हैं और उनसे सत्याग्रह करवाते हैं जिसको रोकने के लिये सरकार को लाखों रुपया खर्च करना होता है । अगर हमें इस सत्याग्रह को रोकना है तो हमारे लिये यह जरूरी होगा कि उस पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है उसकी रकम को कम किया जाये ।

इस वक्त मैं अपने सूबे के मुख्य मन्त्री सरदार प्रताप सिंह कैरों को बधाई और धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि वह राज्य का रुपया खर्च करके केन्द्रीय सरकार का रुपया वसूल कर रहे हैं । उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कदम उठाये हैं जो इस योजना को नाकामयाब बनाना चाहते थे । इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । उनका जो इस काम में कामयाबी मिली है, और जो लोगों को अपने साथ रखने में उनको कामयाबी मिली है वह इस विश्वास के कारण कि वह समझते हैं कि वह हिन्दुस्तान की सरकार के पास जायेंगे और हिन्दुस्तान की सरकार को समझायेंगे कि यह जो पानी की बड़ी योजना है उसके ऊपर जो ५० करोड़ का ब्याज का खर्च लगाया गया है वह ज्यादा है, उसे कम करना होगा और कम करना चाहिये । मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्री मुरारजी और श्री गोपाल रेड्डी जैसे देहाती भाई इसके ऊपर जरूर गौर करेंगे और पंजाब से काबुली की तरह से अपना सूद वसूल नहीं करेंगे ।

इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं । मेरे हल्के में दो ड्रेन हैं, एक ड्रेन नं० ८ और दूसरा है वेस्ट जुमा ड्रेन । इनकी कैपेसिटी ७४० क्यूसेक्स है । पिछली साल इनमें जो पानी आया उससे रोहतक जिले को ७२ लाख रुपये का नुकसान हुआ, और ८३ हजार एकड़ जो खरीफ की जमीन बोई हुई थी उसका नुकसान हुआ, और १३६५६ एकड़ भूमि रबी में नहीं बोयी जा सकी जिससे रबी का ५० लाख रुपये का नुकसान हुआ । दूसरे मानों में एक जिले के अन्दर १,२०,००,००० का नुकसान हुआ । यह रुपया इस जिले को दिया जाना चाहिये । इसी सिलसिले में कुछ और ड्रेन निकाले जा रहे हैं जिनकी कैपेसिटी १४०० क्यूसेक्स है । अगर इस पानी को निकालने का इन्तजाम नहीं किया गया तो यह १ करोड़ २० लाख का घाटा कई करोड़ का जा कर बैठेगा । इसके लिये वित्त मन्त्री महोदय को पंजाब की सरकार को दो, तीन चार करोड़ रुपया देना चाहिये जिससे कि वहां पर वाटर लागिंग का इन्तजाम हो सके ।

**श्री र० द० मिश्र** (बुलन्दशहर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** मैं भी आपका आभारी हूंगा अगर आप थोड़े ही वक्त में समाप्त कर दें ।

**श्री र० द० मिश्र** मेरा इरादा बोलने का नहीं था क्योंकि मेरी तबियत कुछ खराब थी, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे मजबूर कर रहा था कि मुझे फाइनेन्स बिल पर कुछ बोलना चाहिये ।

मैं देखता हूं कि इस फाइनन्स बिल के द्वारा जो हमारी बेसिक आर्थिक नीति है उसमें कुछ बदल हो रहा है । हमारी आर्थिक नीति कुटीर उद्योगों को मदद करने की थी, लेकिन इस बिल के जरिये मैं देखता हूं कि जिस काटेज इंडस्ट्री की मदद करनी चाहिये थी उसको खत्म किया जा रहा है । वह इंडस्ट्री है खडसारी । खडसारी उत्तर प्रदेश

[श्री र० द० मिश्र]

के अन्दर एक खास दस्तकारी है और उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से रुहेलखंड और मेरठ डिवीजन में यह काम बहुत होता है। बिहार में गन्ना होता है लेकिन वहां पर भी यह काम नहीं होता । यह काम उत्तर प्रदेश की रुहेलखंड और मेरठ की दो कमिश्नरियों में ज्यादातर होता है और अब कुछ पंजाब में भी होने लगा है । खंडसारी के काम में बहुत से आदमियों को रोजगार मिलता है । किसानों के बैलों को रोजगार मिलता है । हमारे जिले में एक छोटी सी मिल है, बाकी तमाम एरिया के अन्दर कोई दूसरी मिल नहीं है । १५ लाख की आबादी का जिला है । उस जिले के अन्दर खंडसारी का काम होता है । उसकी वजह यह है कि वहां नहर है जिसकी वजह से वहां गन्ना काफी तादाद में होता है । और उस गन्ने को खपाने के लिये सिवा गुड़ और खंडसारी के दूसरा रोजगार नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह है कि हम यह देख रहे हैं कि कुछ हमारी सरकार की नीति इस तरह की होती जा रही है कि कांग्रेस भी अपनी जगह छोड़ती जा रही है । रुहेलखंड डिवीजन का जहां तक ताल्लुक है, बहुत से इलाकों में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं रहे । जहां तक मेरठ डिवीजन का ताल्लुक है, उसमें भी उसके पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही है । अभी पिछले दिनों चुनाव हुए और कांग्रेस अलीगढ़ और बड़ौत की सीटें हार गई । आखिर हम किस तरह जनता में शान्ति करें कि क्या हमारी नीति है, किस तरह से हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या रोजगार देना चाहते हैं ? हमारा सूबा छः करोड़ से ज्यादा आबादी का है और उसमें किसान ही किसान है । और कोई रोजगार वहां नहीं है । अगर कपड़े की इंडस्ट्री को देखा जाये, तो उसकी मिलें बेकार हो रही हैं । कोई दूसरा रोजगार नहीं है । अभी वहां के चीफ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के मेम्बरों को बुलाया । उन्होंने कहा कि हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, उसके बारे में तमाम कोशिश की जा रही है । लेकिन हम यहां सैन्टर में देखते हैं कि हमारी उस छोटी सी दस्तकारी को भी खत्म किया जा रहा है, जिसके द्वारा थोड़ी सी ताकत उनको मिलती थी । पर कहा यह जाता है कि अब चूंकि इस इंडस्ट्री पर — शूगर पर— इतना टैक्स लग गया है, तो अब तक खंडसारी जीवित कैसे रही । खंडसारी कहां जीवित रही ? इन दो वर्षों में कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो खंडसारी कुछ ज्यादा बनने लगी, वर्ना खंडसारी बनती नहीं थी । उसका गला घोंटा जा रहा था । हमारे लीडर श्री रफी अहमद किदवई ने खंडसारी पर से टैक्स हटवाया । इससे उसमें कुछ थोड़ी सी जान आई, लेकिन फिर भी खंडसारी इन मिलों का मुकाबला नहीं कर सकती । ये मिलें आरगेनाइज्ड प्रापेगेंडा करती हैं । उन का आरगनाइजड स्थान है । खंडसारी वालों का कोई आरगेनाइज्ड स्थान नहीं है । इसलिये वे बेचारे उनके खिलाफ़ कोई काम नहीं कर सकते, इस काम्पीटीशन में आगे नहीं आ सकते । मेरे पास इंडियन शूगर इंडस्ट्री का १९४९ का मेनुअल है । इस में पूंजीपतियों ने सब से पहले प्रोपेगेण्डा किया था कि खंडसारी को खत्म करो । मैं १९४९ की बात कहता हूं । इनकी मीटिंग हुई, जिसमें यह रेजोल्यूशन पास किया गया .

"The Government has imposed control over factory sugar without imposing any control over *gur* and *khandsari* sugar. It is the considered view of the association 'that unless Government bans production of *gur* and *khandsari* in factory zones and also restricts the movement of these by rail and road, it might not be possible for factories to maximise sugar production and reach the target figure.'"

ये पूंजीपति, शूगर मिल वाले, पहले से कोशिश कर रहे हैं । अब मुझे उन्हें बधाई

देनी चाहिये कि आखिर इस साल वे कामयाब हो गये कि इसका गला घोंट दिया । अगले साल यह बिल्कुल खत्म हो जायेगी । अगर हमारे मंत्री लोग खाली अपनी नीति के अनुसार, अपनी प्लानिंग की नीति के अनुसार टैक्स लगाते, तो हमें मंजूर था, लेकिन मेरे पास यह अखबार है । यह १० मार्च, १९५९ का है ।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : अखबार का नाम क्या है ?

श्री र० द० मिश्र : यह १० मार्च १९५९ का हिन्दुस्तान टाइम्स है । हाल में जो मिल एसोसियेशन हुई, उसमें मिल मालिकों ने खुल कर कह दिया कि आपने हमको शक्कर बाहर भेजने की बात कही है और हम बाहर भेज रहे हैं, लेकिन खंडसारी हमारी जान को आ रही है इसका गला घोंटो, वर्ना हम शक्कर बाहर नहीं भेज सकते । यह प्रोपेगेण्डा है और हमारे कांग्रेस के मिनिस्टर इस प्रोपेगेण्डा के अधीन चारों खाने चित्त आ गये । इसके अधीन आ कर वे टैक्स लगा रहे हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : तो फिर इस्तीफा दे दीजिये ।

श्री र० द० मिश्र : अगर यह प्रोपेगेण्डा और दबाव न होता, तो हमें मंजूर था । अब भी हमें मंजूर है, क्योंकि हमने कांग्रेस में रहना है और कांग्रेस का साथ देना है । अगर कांग्रेस गलती करेगी, तो हम उसकी गलती सुधारेंगे अगर मिनिस्टर ग़लती करेंगे, तो हम उनकी ग़लती सुधारेंगे और अगर दूसरे ग़लती करेंगे, तो हम उनकी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे । हम समझते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है, जो देश को आगे ले जा सकती है । इसीलिये हम कांग्रेस में हैं । लेकिन मंत्रीगण के सामने हम सच्ची बात रखे बगैर नहीं रह सकते । मोरारजी साहब हमारे पुराने नेता हैं । उनकी जयजयकार हमने बोली है । वह बम्बई के मिनिस्टर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें देखा हो, या न देखा हो, उन्हीं का नाम ले कर हमने इलाकों में कांग्रेस का प्रोपेगेण्डा किया, उन्हीं की बातें बतलाई । लेकिन आज हम अमल में देखते हैं कि क्या हो रहा है । क्या उन्होंने हमसे बातें कहीं और क्या हो रहा है ? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खंडसारी खाते हैं । मैं खंडसारी और चीनी दोनों खाता हूं । लेकिन हमारे नेता खंडसारी का प्रयोग करते हैं और खंडसारी का ही गला घोंटा जाये, यह मेरी समझ में नहीं आता । चूंकि मेरी समझ में यह नहीं आता, इसलिये मैं उनके सामने रख रहा हूं कि यह खंडसारी की दस्तकारी उत्तर प्रदेश के गरीब आदमियों को रोजगार देती है और जिस जिले से मैं आता हूं, अगर मैं उसकी स्थिति उन के सामने न रखूं, तो यह समस्या उनकी समझ में नहीं आयेगी, क्योंकि न बम्बई में और न बंगलौर में यह पैदा होती है ।

अब सवाल यह है कि यह जीवित कैसे रह गई ।

श्री फीरोज गांधी (रायबरेली) : तम्बाकू को बन्द करा दिया, अब उसको भी बन्द करा दे ।

श्री र० द० मिश्र : तम्बाकू की बात मैं कहता नहीं हूं । तम्बाकू का सवाल छोड़िये ।

खंडसारी जीवित तब रह सकती है, जब बाजार में कोई गुंजाइश हो । अगर उसके लिये गुंजाइश नहीं छोड़ते, तो खंडसारी कैसे चल सकती है । दो बरसों में क्यों खंडसारी थोड़ी सी चल गई ? वह महज इसलिये कि सरकार ने मिल शुगर का टैक्स बढ़ा दिया जिससे खंडसारी में नफ़े का मार्जन कुछ बढ़ गया और लोग उसमें काम करने लगे । जब लोगों को किसी इंडस्ट्री में नफ़ा दिखाई देता है, तो वे उसको बढ़ाते हैं । हमने लोगों को कहा कि अपने पुराने तरीकों में बदल करो, तो सरकार भी मदद करेगी, क्योंकि

[श्री र० द० मिश्र]

प्लानिंग कमीशन की किताब हमारे पास है—इतनी मोटी है। इसमें लीडरों के वादे हैं कि खंडसारी को हम तरक्की देंगे। इसको रुपया भी देंगे। एक बोर्ड भी बना—खादी बोर्ड भी बना। हमने फिर दबाव डाला, तो उस बोर्ड का नाम कमीशन रख दिया गया। उसने भी एक किताब निकाली है। यह छपी हुई किताब है और इसमें पूरे फैक्ट्स एंड फीगर्ज हैं। खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से छापी गई वह किताब "गुड़ एण्ड खंडसारी इंडस्ट्री" है। इसमें तमाम फैक्ट्स मौजूद हैं। एक परफ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस इंडस्ट्री को तरक्की देने की बात की जाय और फिर उसका गला घोटा जाय, तो फिर हम अपनी कास्टीच्युएन्सी में जाकर लोगों को क्या समझायें कि वे क्या रोजगार करें, किस तरह से वे अपना पेट भरें। हमारे यहां आफत आई, जलजला आया, बारिश और तूफान आये और उनकी इकानमी घटी। हमारी कास्टीच्युएन्सी जमना पार है। वे लोग कहते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपको गेहूं अठारह रुपये मन मिलती है, हमको यहां जमना पार २८ रुपये मन मिलती है। यह दस रुपये का फर्क है। वे कहते हैं कि आप पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, आपको और मिनिस्टरों को गेहूं दस रुपये मन सस्ती मिलती है।

श्रीमन्, आप ने घंटी बजादी है। मैं डिस-ओबे नहीं करना चाहता और आपका सुझाव अदा करता हूं।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) उपाध्यक्ष महोदय, आज जब इस बिल पर विचार हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि कर और करदाता दोनों के बारे में कुछ न कहूं। यह मैं समझता हूं कि एक देश में निर्माण करने में कर की जरूरत है और निर्माण-काल में वह एक आहुति है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कर आहुति की शक्ल में कर दाता कब तक दे। अगर हम देखें, हर साल बजट पेश होने से पहले हिन्दुस्तान का मामूली इन्सान तकरीबन सांस रोक कर इन्तजार करता है और धीरे धीरे उस की कर देने की तमाम शक्ति हीन होती रही है। और अब वह ऐसी हालत में पहुंच चुका है कि उस की हड्डियों का आखिरी कतरा-ए-खून आप कर की शक्ल में लें, तो वह दे तो जरूर देगा—क्योंकि उस को देश प्यारा है, वह देश का निर्माण करना चाहता है, लेकिन देने की शक्ति और सीमा अब उस में नहीं है। इस बात को मेरे ख्याल में माननीय मन्त्री जी भी मानेंगे। सवाल यह आता है कि आखिर कर अगर न लिया जाये, तो देश का निर्माण कैसे हो। इनकमटैक्स एरियर्ज के बारे में पूर्ववक्ताओं ने काफी बातें कही। उस में इवेजन कितना हुआ, चोरी कितनी हुई, उस का तो हिसाब शायद लगाना मुश्किल है, लेकिन बकाया रुपए के बारे में एक अनस्टार्ड क्वेस्चन के जवाब में बताया गया कि ३१ मार्च १९५६ को यह रुपया २३३·५९ करोड़ था। उस के बाद सरकार ने उस को वसूल करने की कोशिश की तो उस की कोशिश के फलस्वरूप ३१ मार्च, १९५७ को वह रुपया २६७ ३३ करोड़ हुआ। इसके बाद सन् १९५७ में फिर यह कोशिश की गई कि इस रुपये को वसूल किया जाए। ३१ मार्च १९५८ को यह रुपया २८७ करोड़ हो गया। मैं समझता हूं कि चाहे कोशिश की जा रही है लेकिन यह बढ़ता ही जा रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं मन्त्री महोदय से पूछूं कि कि आखिर ये कौन देश भक्त हैं, जो दे नहीं रहे हैं? ये जो ग्रेटेस्ट पैट्रियोट हैं, उनका नाम कभी कभी हमारे सामने आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वसूली का तरीका कौन सा अपनाया गया है? क्यों इतने कमजोर साधन इस रकम को वसूल करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं? मैं ने पंजाब में वसूली का तरीका देखा है। वहां पर हमारे लोग करदाताओं के पास जाकर गिड़गिड़ाते

हैं और कहते हैं कि दे डालो यह रुपया और उन से इस के लिए अनुनय-विनय-करते हैं। एक तरफ तो इस रुपये को वसूल करने के लिए इस तरीके का आश्रय लिया जाता है और दूसरी तरफ खुशहाली टैक्स, बैटरमेंट लेवी को वसूल करने के लिए लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं। यह किस तरह की कर-नीति है, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई कड़ी नीति अपनाई जाए जिस से यह रुपया जो बकाया है उसे वसूल किया जा सके और इस रुपये को देश के निर्माण में लगाया जा सके। अगर आप देश का निर्माण करने के लिए आम जनता से टैक्सों पर टैक्स वसूल करते जाएं और दूसरी तरफ इस बकाया को वसूल करने का प्रबन्ध न करें और इसका गरीब जनता को पता चल जाए कि अरबों रुपया इनकम टैक्स का बकाया पड़ा हुआ है तो वह जरूर आप से कहेगी कि आखिर कुर्बानी हम से ही क्यों मांगी जा रही है? हम करदाता हैं और हम और रुपया भी टैक्सों की शक्ल में देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम चाहते है कि देश का निर्माण हो, लेकिन उसकी सीमा कहां तक जाती है, यह हम पूछना चाहते हैं? आपकी इंसाफ की तराजू में एक तरफ तो वह गरीब कर-दाता है, वह हिन्दुस्तान का मामूली इंसान है जो कि सभी टैक्स आपको अदा कर देता है, और दूसरी तरफ वह एक सरमायेदार है जो कि टैक्स की बकाया रकम अदा नहीं कर रहा है और उसके साथ आप सख्ती का सलूक नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में सख्ती से काम लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरा ख्याल है कि यह सारा रुपया एक न एक दिन बट्टे खाते में आपको डालना पड़ेगा, यह रुपया आपको मिलेगा नहीं।

खंडसारी के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसके बारे में मेरे एक मित्र ने ठीक ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं तमाम चीजों की वजह से एक तरफ तो चीनी के कारखाने वाले मुनाफा करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ शूगर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए रिलीफ की बात की जाती है, तो कह दिया जाता है कि चार रुपया और पांच रुपया हम रिलीफ देने के लिये तैयार है। मैं समझता हूं कि इन कारखाने वालों ने खंडसारी का गला घोंटने की कोशिश की है और इस में वे कामयाब हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को जो कंसेशन उन्होंने खंडसारी उद्योग को दिये हैं, उस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वे सोचें कि क्या इतना होने पर भी इस उद्योग को जीवित रखा जा सकता है? आंकड़ों से हो सकता है कि वह यह साबित कर दे कि वह जीवित रहेगा लेकिन अगर आंकड़ों पर न जा कर असलियत पर वह जायें तो उनको पता चलेगा कि यह उद्योग जीवित रह नहीं सकता है। यह उद्योग उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि सारे भारत के लिए बड़े महत्व का है। मैं चाहता हूं कि आप इस उद्योग की ओर अधिक ध्यान दें और इसको जीवित रखने की भरसक कोशिश करें।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरठ जिले में अभी एक चुनाव हुआ है। पिछली बार जब वह चुनाव हुआ था तो एक व्यक्ति २६०० वोटों से जीता था। उसके बाद इलैक्शन पेटिशन में वह हार गया और आज दो साल के बाद जब फिर चुनाव हुआ तो वह १३,००० वोट से जीता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि आखिर यह नीचे से जमीन क्यों खिसकती जा रही है क्यों लोगों का यह विश्वास आप पर से उठता जा रहा है। यह हालत उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात मैं नहीं कहता हूं। लेकिन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में यह हालत क्यों हुई है, इस पर आप विचार करें और कारणों का पता लगायें तो आपको पता चलेगा ——

**चौ० रणबीर सिंह** (रोहतक) पंजाब में जीत हुई है।

**श्री स० म० बनर्जी** : पंजाब में जीत हुई है, ठीक है और मैं चाहता हूं कि और जीत

[श्री स० म० बनर्जी]

हो और और भ्रष्टाचार किया जाए ताकि असली चोर ये सब बातें लोगों के सामने आ सकें।

वेतन आयोग का सवाल भी हमारे सामने है और वह बैठा हुआ है। इसी तरह से टैक्सटाइल वर्कर्स के लिए, शूगर वर्कर्स के लिए, सिमेंट के लिए, हमारे पत्रकार बन्धुओं के लिए भी बोर्ड बैठे हैं। ये लोग भी करदाता हैं और ये आशा करते हैं कि इनको भी करों में हिस्सा मिलना चाहिये। आप कहते हैं कि पे कमिशन की रिपोर्ट जून में निकलने वाली है। मैं समझता हूं कि इस देश की कुछ ऐसी परम्परा है कि यहां पर कमेटिया बैठती है, कमिशंस बैठते है और सो जाते हैं। जब दो एक साल के बाद जगाने की कोशिश की जाती है उस के बाद फिर वे काम करना शुरू कर देते है। एक ओर तो करों की वजह से लोगो की पीठ टूटती जा रही है, उन पर करो का बोझ बढ़ता जा रहा है दूसरी तरफ जब रिलीफ की माग की जाती है तो कह दिया जाता है कि नही, वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी आई नही है और जब तक वह आती नहीं है तब तक कुछ नही किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि आपको साधनो की जरूरत है, आपके पास रुपया आना चाहिये, लेकिन देखना यह है कि इसको वसूल करने के लिये आप कौन से साधन अख्तयार करते है।

आपके पास रुपया आए, इसके लिए जब बैंकों को नैशनलाइज करने की बात की जाती है और कहा जाता है कि इस से आपको रुपया मिलेगा तो आप कह देते हैं कि समय ठीक नहीं है। क्यों ठीक नही है यह मैं जानना चाहता हू। आज इन बैंकों का व्यवहार किस प्रकार का है। इस दिल्ली शहर में अभी अभी नैशनल एंड ग्रिंडले बैंक ने कर्मचारियो के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि जब भी कोई एडवर्स रिपोर्ट किसी की दी जायेगी या लिखी जाएगी तब उन्हें बहस करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस एग्रीमेंट को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद एम्प्लाईस को एडवर्स रिपोर्ट दी गई। इसके खिलाफ जब प्रदर्शन हुए तो छः आदमियों को दिल्ली में ही सस्पेंड कर दिया गया और उस सस्पेंशन के खिलाफ कोई आवाज न उठा सके इसके लिए आज पुलिस दस दिन से लारियों में मैजिस्ट्रेट को ले कर के उस बैंक के चारों तरफ घूमती फिरती है और इस उद्देश्य से वहां बैठी है कि अगर कोई विरोध किया गया तो उनकी खबर ली जा सके। अगर दिल्ली शहर में ही जहां पर कि हमारे मंत्री महोदय रहते हैं, बैंक वालों की यह मजाल हो कि एग्रीमेंट को तोड़ें तो दूसरी जगहों का क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर आज इन हालात में लोग कहते हैं कि बैंकों का नैशनलाइजेशन होना चाहिये, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वे क्या जुर्म करते हैं?

आपने इन्श्योरेंस को नैशनलाइज किया, अच्छा किया। एक मूदड़ा काड हुआ और इस तरह के और कई कांड हुए होंगे, लेकिन जो नैशनलाइजेशन किया गया वह ठीक ही किया गया। मूदड़ा कांड में जो लोग इनवाल्व्ड थे, उन के खिलाफ इनक्वायरी चल रही है और मुझे मालूम हुआ है कि —पता नही कहां तक सच है — कि यू० पी० एस० सी० ने उन्हें एग्जानरेट कर दिया है। कोई बात नही लेकिन इनश्योरेंस को नैशनलाइज तो किया गया, जनरल इनश्योरेंस को और वह एक बड़ी बात थी। इसी तरह से अगर बैंकों का नैशनलाइजेशन हो तो काफी रुपया आपको मिल सकता है।

आप राम राज्य की बात करते है। पहले भी एक बार आपने की थी। हमने उसको सुना था। उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी और उस वक्त हम राम राज्य का स्वप्न देखते थे। मैं भी सोचता था कि कब राम राज्य आयेगा जबकि देश की सब मुसीबतें हल होंगी, इस देश पर हमारा तिरंगा झंडा फहरायेगा लोग चौपालों

पर बैठ करके राम राज्य की बात किया करेंगे। लेकिन आज हम देखते क्या हैं? आज लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तन ढकने के लिए कपड़ा उनके पास नहीं है, रहने के लिए मकान उनके पास नहीं है। क्या राम-राज्य की यह परिभाषा है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय अपने हाथ में कर का धनुष लेकर और ४० करोड़ वानरों की सेना बना कर, उनको कहें कि पेड़ों पर रहो, फल इत्यादि खाओ, न मकान में रहो और न तन पर कपड़ा पहनो? अगर यही राम-राज्य की आपकी परिभाषा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आज हालत क्या है? कपड़े के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। कपड़े की गांठें तो बाजार में हैं और कपड़े के व्यापारी चाहते हैं कि कोई नंगा ऐसा मिले जिसकी मुट्ठी में पैसा हो। लोगों के पास कपड़ा खरीदने के लिये पैसा ही नहीं है। कारखाने बन्द हो रहे हैं। ऐसी सूरत में करदाताओं का यह हक है कि वे आपसे पूछें कि आप करों का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि किस तरह से लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। आज उस सीमा तक हम पहुंच चुके हैं जब कि और कुर्बानी करने की ताकत लोगों में नहीं रह गई है। उनकी जेबें इतनी बुरी तरह से कतरी जा चुकी हैं कि आज उनकी जेबों में न एक नया पैसा है और न ही पुराना पैसा। मुझे एक मिडिल क्लास वाले मामूली बैंक क्लर्क ने कहा कि मिडिल क्लास की आज हालत ऐसी है कि पहली तारीख को उसको तनख्वाह मिलती है, पहली से पांच तारीख तक वह कैपिटलिस्ट होता है, पांच तारीख से दस तारीख तक वह सोशलिस्ट होता है, दस से पंद्रह तारीख तक या बीस तारीख तक वह कम्युनिस्ट होता है और उसके बाद टेररिस्ट।



**वित्त उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: आप अपनी बात कह रहे हैं क्या?

**An hon. Member**: What about Congress?

**Shri S. M. Banerjee**: Capitalist within brackets Congress.

**उपाध्यक्ष महोदय**: अगर माननीय सदस्य श्री बनर्जी के बारे में पूछना चाहते हैं तो वह अप्रासंगिक है।

**श्री स० म० बनर्जी**: मगर मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा लैफ्ट के साथ हूं। मैं लैफ्ट के साथ इस वजह से हूं कि पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा होकर कहता है कि Keep to the left because left is the safer side.

15 hrs.

**Shri Raghunath Singh (Varanasi)**: He is guided by the traffic-police and not by the leaders.

**श्री स० म० बनर्जी**: इसलिये लेफ्ट के साथ रहना मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज आप इसको अच्छे तरीके से सोचिये कि आखिर कैसे लोगों को रिलीफ दिया जाये। सेल्स टैक्स के बारे में हाहाकार मचा हुआ है। सेल्स टैक्स की लड़ाई जब उत्तर प्रदेश में हुई तो क्या डिमान्ड उनकी थी। उनका कहना था कि एक यूनिफार्म बेसिस पर सेल्स टैक्स होना चाहिये। प्रोफेसर पी० एस० लोकनाथन ने जो कि अर्थशास्त्र के पंडित हैं उन्होंने कहा था कि बिजिनेस को बचाने का यह तरीका होगा कि हर एक प्रान्त में एक तरह का सेल्स टैक्स हो। मैं जानता हूं कि शायद केन्द्रीय सरकार इससे सहमत है लेकिन वह कहती है कि राज्य सरकारें नहीं मानतीं। उनसे आप कहिये कि आखिर अगर बिजिनेस को जिन्दा रखना है तो सेल्स टैक्स यूनिफार्म बेसिस पर होना

[श्री स० म० बनर्जी]

चाहिये। सेल्स टैक्स के जो प्रोसीजर हैं वे इतने काम्प्लिकेटेड हैं कि हमारे बिजिनसमैनों का बिजिनेस चौपट हो जाये अगर वह सेल्स टैक्स के बहीखोते को पूरा करें। आज बिजनेसमैन करता क्या है? रिश्वत देता है, नाम बदलता है, इवेड करने की कोशिश करता है, और इससे मेरा ख्याल है कि देश का कल्याण नहीं हो रहा है। आपने टेक्सटाइल में सेल्स टैक्स को एक्साइज ड्यूटी के साथ मर्ज कर के, सोर्स प्वाइंट पर लगा कर बहुत अच्छा किया है और इसके लिये लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है। मैं समझता हूं कि देश भर में जो कपड़ा मर्चेंट हैं उन्होंने कहा है कि यह बहुत अच्छा फैसला हुआ है।

आज देश में बेकारी बढ़ती जा रही है; बेकारी के बारे में कहा गया कि उनको ५० करोड़ बेकारी भत्ता दिया जाय। इस पर भी तो आखिर आप सोचिये। यह देश सबका देश है। मैं अगर विरोध कर रहा हूं तो इस वजह से नहीं कि मैं कोई पैदाइशी विरोधी हूं। मैं इस चीज को सोचता हूं। मेरा कोई पेशा नहीं है विरोध करना। सिर्फ एक नागरिक की हैसियत से मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। आप करदाता की तरफ देखिये। अगर हम और आप वाकई करदाता की मदद करना चाहते हैं तो हम को और आप को मिल कर दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को कामयाब करना है। मैं समझता हूं कि उसकी कामयाबी में देश का भला है और अगर तमाम देश का भला होता है तो मैं समझता हूं कि हमारे बालबच्चों की मुस्कराहट कायम रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन चीजों पर विचार करें और सोचें कि किस तरीके से रिलीफ दिया जाय उस गरीब आदमी को जिस की कमर टूट रही है।

15.03 hrs.

## BUSINESS OF THE HOUSE

**The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):** With your permission, Sir, I want to announce a slight change in the order of Government business for tomorrow, Thursday the 23rd April, 1969. The Indian Lighthouse (Amendment) Bill will be taken up for consideration and passing before taking up the motion for reference of the Arms Bill to a Joint Committee.

15.03½ hrs.

## FINANCE BILL—*contd.*

**The Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** Sir, I have heard with great attention and respect all that has been said on the Finance Bill by all the hon. Members who have spoken on this subject. As it is the convention or the rule that every subject can be discussed on the Finance Bill, the discussion has been very varied and interesting. But it is not possible for me to cover all those subjects, naturally, and therefore, I hope the hon. Members will bear with me if I do not refer to matters which I will not be able to refer within the time at my disposal. I want, in this connection, to take the advice of my hon. friend, Shri Bharucha, who said that the Ministers should not speak much, they should speak less. I shall certainly try to follow him in this matter at any rate though I am not able to agree with him on many other things.

Before I refer to other matters I should like to refer to one matter which has been a result of what I had referred to when I spoke last. That is as regards the mentioning of the expenditure on Parliament. My culture and refinement have also been doubted. I have no quarrel with the person who does it but I wonder sometimes when I meet him—I have been meeting him many times for the last many year—though there has been a difference between him and me about the re-organisation of